

TEST 04
Polity
(भारतीय राजव्यवस्था)

समय— 2 घंटे

उम्मीदवार का अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न—पुस्तिका

UPPSC 2026-27

प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला

A

पूर्णांक –200

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ ले

महत्वपूर्ण निर्देश

1. इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों पर समान अंक हैं। सभी प्रश्नों का प्रयास करें।
2. परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद, आपको अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला पुस्तिका के ऊपरी दाएं कोने पर छपी हुई है। यदि आप इस पुस्तिका में कोई त्रुटि पाते हैं, तो इसे तुरंत उसी श्रृंखला की पूरी पुस्तिका से बदलवा लें।
3. यदि मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकृति की किसी भी प्रकार की गलती है, तो प्रश्नों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में से अंग्रेजी संस्करण को मानक माना जाएगा।
4. आपको इस पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखना चाहिए। प्रश्न-पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
5. उत्तरों को चिह्नित करने के लिए निरीक्षक द्वारा आपको अलग से एक उत्तर पत्रक प्रदान किया जाएगा। आपको अपना नाम, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला और अन्य विवरण दिए गए उत्तर पत्रक के पृष्ठ-2 पर दिए गए स्थान में लिखना होगा, ऐसा न करने पर आपका उत्तर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको अपना रोल नंबर और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, ए, सी या डी को कोड करना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न पुस्तिका के ऊपरी दाएं कोने पर ब्लैक / ब्लू इंक बॉलपॉइंट पेन से आपके पृष्ठ-2 पर दिए गए स्थान पर मुद्रित है। उत्तर पत्रिका यदि आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की सही श्रृंखला को एनकोड नहीं करते हैं या एनकोड करने में विफल रहते हैं, तो आपकी उत्तर पुस्तिका का सही मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
7. इस पुस्तिका में प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में छपे हैं। प्रत्येक प्रश्न में पाँच उत्तर होते हैं: (ए), (बी), (सी), और (डी)। आपको केवल एक सही उत्तर का चयन करना है और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करना है। यदि आपको लगता है कि एक से अधिक सही उत्तर हैं, तो उस उत्तर को चिह्नित करें जो आपको सबसे अच्छा लगता है। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनें। आपके कुल अंक उत्तर पत्रक में आपके द्वारा चिह्नित सही उत्तरों की संख्या पर निर्भर करेंगे। उत्तर पत्रक में, प्रत्येक प्रश्न के सामने पाँच गोल (A), (B), (C), और (D)। प्रश्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए अपनी पसंद का केवल एक/नीली स्याही के बॉलपॉइंट पेन से चिह्नित करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर का चयन करें और उसे अपनी उत्तर पत्रिका में लिखित में लिखित में लिखित करें।
8. उत्तर पत्रक में, प्रत्येक प्रश्न के सामने पाँच वृत्त हैं: (A), (B), (C), और (D)। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए अपनी पसंद का केवल एक गोला काली/नीली स्याही के बॉलपॉइंट पेन से चिह्नित करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर का चयन करें और उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखित करें। यदि आप एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त चिह्नित करते हैं, तो उत्तर को गलत माना जाएगा। उत्तर पत्रक में उत्तर अंकित करने के लिए केवल काली/नीली स्याही के बॉलपॉइंट पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी मिटा या परिवर्तन की अनुमति नहीं है।
9. आपको प्रश्न-पुस्तिका से किसी भी शीट को हटाना या फाड़ना नहीं चाहिए। आपको परीक्षा के दौरान इस प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा हॉल से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के बाद, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका निरीक्षक को सौंपनी होगी। इसके बाद, आपको प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है।
10. उपरोक्त किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर आप ऐसी कार्रवाई या दंड के लिए उत्तरदायी होंगे जो आयोग अपने विवेकानुसार तय कर

ध्यान दें: अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर छपा है।

1 KREDOZ IAS ACADEMY www.kredoz.com Download App: kredoz – The learning App

Phone – 9582225699, 9648866818 Kredoz Mentorship Library Wazirabad Gali No. 06 Near Munafa Bazar, Sangam Vihar Road

Head Office – Plot No. 8, 2nd Floor, Niti Khand 1, Near Indrapuram Metro Station, Gali No 8/1 Wazirabad, Delhi 110084

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना (Preamble) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रस्तावना में उल्लिखित 'न्याय' (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) के आदर्श को रूसी क्रांति (1917) से प्रेरित होकर लिया गया है।
2. केशवानंद भारती वाद (1973) से पहले सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट मत था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है।
3. प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्तियों का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, और यह गैर-वादायोग्य (Non-justiciable) है यानी इसके प्रावधानों को अदालतों में लागू नहीं कराया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

2. भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए (कौन सा/से सुमेलित है/हैं):

1. चौथी अनुसूची: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन
 2. आठवीं अनुसूची: दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान
 3. ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (29 विषय)
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) के दायरे में उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है?

1. विदेश यात्रा का अधिकार
2. त्वरित न्याय (Speedy Trial) का अधिकार
3. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा उपचार का अधिकार
4. प्रदूषणमुक्त जल और वायु का अधिकार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

4. भारतीय संविधान के भाग-IV में वर्णित 'समान नागरिक संहिता' (Uniform Civil Code - अनुच्छेद 44) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निदेशक तत्व है जिसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
 2. संविधान लागू होने के समय से ही देश के सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य रूप से लागू करना संवैधानिक बाध्यता थी।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

5. भारतीय संसद में धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद 110) के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है (असत्य है)?

- (a) धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं।
- (b) धन विधेयक को पुनरुत्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) आवश्यक होती है।
- (c) राज्यसभा के पास धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है, वह अधिकतम 14 दिनों तक इसे रोक सकती है।
- (d) यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती या अपनी सिफारिशें भेजती है, तो लोकसभा के लिए राज्यसभा की उन सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है।

6. उच्चतम न्यायालय की 'सलाहकार क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction - अनुच्छेद 143) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति लोक महत्व के किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं।
2. यदि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति को अपनी सलाह देना अनिवार्य (Mandatory) होता है।
3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी (Binding) नहीं होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

7. राज्य के राज्यपाल की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (अनुच्छेद 213) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) राज्यपाल यह अध्यादेश किसी भी समय जारी कर सकते हैं, चाहे राज्य विधानसभा सत्र में ही क्यों न हो।
- (b) राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की पुनर्बैठक के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है।
- (c) राज्यपाल अपनी इच्छा से कभी भी अध्यादेश वापस ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें राज्य मंत्रिमंडल की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती।
- (d) इस अध्यादेश की संविधानी वैधता की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती।

8. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय स्रोतों को मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य में किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है?

- (a) राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - अनुच्छेद 243-I)
- (b) जिला योजना समिति (District Planning Committee)
- (c) राष्ट्रीय विकास परिषद
- (d) राज्य लोक सेवा आयोग

9. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency - अनुच्छेद 352) के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान सही है?

- (a) अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, इसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
- (b) अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते।
- (c) राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा यह घोषणा कर सकते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार भी निलंबित रहेगा।
- (d) उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

10. भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. संविधान के कुछ विशिष्ट प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार आदि) में संशोधन

के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) आवश्यक है।

- 2. संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में स्पष्ट रूप से वर्णित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

11. भारतीय संसद में 'कटौती प्रस्तावों' (Cut Motions) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. कटौती प्रस्ताव केवल 'लोकसभा' में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं, क्योंकि अनुदान की मांगें लोकसभा के समक्ष रखी जाती हैं।

- 2. 'नीतिगत कटौती प्रस्ताव' (Policy Cut Motion) का उद्देश्य सरकार की नीति से असहमति व्यक्त करना होता है, जिसके तहत मांग की राशि को घटाकर ₹1 कर दिया जाता है।

- 3. 'मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव' (Economy Cut Motion) के तहत मांग की राशि में किसी विशिष्ट और निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

12. संसद की 'प्राक्कलन समिति' (Estimates Committee) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- 1. यह संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं (राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता)।

- 2. इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और परंपरा के अनुसार अध्यक्ष हमेशा 'विपक्ष' के दल से ही चुना जाता है।

- 3. यह समिति न केवल बजट अनुमानों की जांच करती है, बल्कि यह भी सुझाव देती है कि प्रशासन में कैसे मितव्ययिता और दक्षता लाई जाए।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय की 'पुनरावलोकन की शक्ति' (Power of Review) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय या आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति प्राप्त है।
2. संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की इस पुनरावलोकन की शक्ति को पूर्णतः समाप्त या प्रतिबंधित कर सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

14. किसी राज्य में 'विधान परिषद' (Legislative Council - अनुच्छेद 169) के सृजन या उत्सादन (Abolition) की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) राज्य विधानसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या अंत कर सकती है।
(b) इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (2/3 बहुमत) की आवश्यकता होती है।
(c) इस प्रक्रिया के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है और राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने से पहले राज्यपाल की संस्तुति जरूरी है।
(d) यह पूरी तरह से राज्य विधानसभा का आंतरिक मामला है, इसमें संसद की कोई भूमिका नहीं होती।

15. केंद्र-राज्य विधायी संबंधों (Legislative Relations - अनुच्छेद 245-255) के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में संसद को राज्य सूची (State List) के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है?

1. यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है (अनुच्छेद 249)।
2. यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके संसद से अनुरोध करें कि वे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएं (अनुच्छेद 252)।
3. भारत के बाहर किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या कन्वेन्शन को लागू करने के लिए (अनुच्छेद 253)।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

16. संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule) की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी जारी होने की तिथि से दो माह के भीतर साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही जारी रखा जा सकता है, बशर्ते हर 6 महीने पर संसद का अनुमोदन मिलता रहे।
3. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास आ जाती है और विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

17. भारत के 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' (Chief Election Commissioner) को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी समय बिना किसी प्रक्रिया के हटाया जा सकता है।
(b) उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग जैसे प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
(c) उन्हें हटाने के लिए संसद के साधारण बहुमत और देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है।
(d) उन्हें हटाने की शक्ति केवल प्रधानमंत्री के पास होती है।

18. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा प्रावधान अनिवार्य (Mandatory) प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि स्वैच्छिक (Voluntary) है?

- (a) पंचायतों के तीनों स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) पर प्रत्यक्ष चुनावों का आयोजन
(b) पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण
(c) संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों (MP/MLA) को पंचायत के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व (सदस्यता) देना
(d) पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करना

19. भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती।
 2. यदि कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास यह संवैधानिक शक्ति है कि वे उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं (विटो का प्रयोग कर सकते हैं)।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

20. भारतीय राजव्यवस्था में 'महान्यायवादी' (Attorney General of India - अनुच्छेद 76) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही नहीं है (असत्य है)?

- (a) वे भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी माने जाते हैं।
- (b) उनकी योग्यता वही होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है।
- (c) उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और उन्हें मतदान करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
- (d) वे अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करते हैं।

21. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 'रिट्स' (Writs) के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर उसके शरीर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश।
2. उत्प्रेषण (Certiorari): किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिए गए निर्णय को रद्द करने के लिए जारी आदेश।
3. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कब्जे करने वाले व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी किया जाता है कि वह किस प्राधिकार (Authority) से उस पद पर है।

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

22. भारतीय संविधान के भाग-IV में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत कौन-से गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles) शामिल हैं?

1. ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40)
2. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 43)
3. काम, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार (अनुच्छेद 41)
4. गोहत्या निषेध और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारना (अनुच्छेद 48)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

23. भारत के राष्ट्रपति की 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power - अनुच्छेद 72) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति की यह शक्ति न्यायिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका की एक विशेष शक्ति (Executive Power) है, जिसके तहत वे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकते हैं।
 2. राष्ट्रपति मार्शल लॉ (सैन्य न्यायालय) द्वारा दी गई सजा को भी माफ या कम कर सकते हैं।
 3. राष्ट्रपति के क्षमादान के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है यदि यह निर्णय प्रथम दृष्टया मनमाना, पक्षपातपूर्ण या mala fide पाया जाए।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

24. भारतीय संसद में प्रस्तुत होने वाले 'साधारण विधेयक' (Ordinary Bill) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
- (b) इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) का होना अनिवार्य है।
- (c) यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।
- (d) राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 6 माह की अवधि तक रोक सकती है।

25. राज्य के राज्यपाल की 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (अनुच्छेद 213) और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति (अनुच्छेद 123) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

- (a) राज्यपाल कभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल आपातकाल में कर सकते हैं।
- (b) राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Instruction) की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रपति के मामले में आवश्यक नहीं है।
- (c) राज्यपाल के अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, जबकि राष्ट्रपति के अध्यादेश की हो सकती है।
- (d) राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती।

26. भारतीय संविधान के 'मूल अधिकार क्षेत्र' (Original Jurisdiction - अनुच्छेद 131) के तहत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस विवाद की सीधी सुनवाई कर सकता है?

- 1. केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।
 - 2. भारत सरकार और किसी राज्य / राज्यों तथा दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद।
 - 3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का आपसी जल-बंटवारे से जुड़ा विवाद।
 - 4. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का ऐसा कानूनी विवाद जिसमें कोई विधिक अधिकार (Legal Right) शामिल हो।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
- (a) केवल 1, 2 और 4
 - (b) केवल 1 और 3
 - (c) केवल 2, 3 और 4
 - (d) 1, 2, 3 और 4

27. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (नगरपालिकाओं से संबंधित) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 1. इस संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग IX-A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय (Functional Items) दिए गए हैं।
- 2. नगरपालिकाओं के तीन प्रकार होते हैं—नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम।

3. नगरपालिकाओं के सभी स्तरों के अध्यक्षों के चुनाव के लिए संविधान ने प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

28. भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में 'राज्यों के अनुसमर्थन' (Ratification by States) के बिना संसद अकेले निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन कर सकती है?

- (a) राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया और उसका तरीका (अनुच्छेद 54, 55)
- (b) संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद 73)
- (c) संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व (चौथी अनुसूची)
- (d) नए राज्यों का निर्माण या उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)

29. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) और 'राज्य लोक सेवा आयोग' (SPSC) के सदस्यों को उनके पद से हटाने और निलंबित करने की शक्ति का प्रावधान है?

- (a) अनुच्छेद 315
- (b) अनुच्छेद 317
- (c) अनुच्छेद 320
- (d) अनुच्छेद 324

30. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, और उसमें कौन-से शब्द जोड़े गए थे?

- (a) दो बार; 'धार्मिक' और 'अखंडता'
- (b) एक बार; 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता'
- (c) एक बार; 'लोकतांत्रिक', 'गणराज्य' और 'बंधुता'
- (d) प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं किया गया है।

31. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 'स्वतंत्रता के छह अधिकारों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों (शत्रु या मित्र) को नहीं।
2. इन अधिकारों पर राज्य 'भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार' के आधार पर उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगा सकता है।
3. आपातकाल के दौरान 'युद्ध या बाह्य आक्रमण' के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर ये अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर लगने पर स्वतः निलंबित नहीं होते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

32. भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है (कौन सा गलत है)?

- (a) अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
- (b) अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन
- (c) अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code)
- (d) अनुच्छेद 48A: कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण

33. भारतीय संसद और उसके सदस्यों के 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में संसद के विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह प्रावधान किया गया है कि ये वही विशेषाधिकार होंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के पास ब्रिटेन में संविधान लागू होने के समय थे।
2. संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद के भीतर सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

3. सदन के सत्र के दौरान या सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी सांसद को दीवानी मामलों (Civil Cases) में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

34. राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त आवश्यक है?

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
 2. उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
 3. वह उस राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति की जा रही है (यह एक अनिवार्य संवैधानिक बाध्यता है)।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

35. उच्चतम न्यायालय की 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) और जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत में जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा के जनक न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को माना जाता है।
2. PIL के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था समाज के किसी पीड़ित वर्ग या जनहित के मुद्दे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 32) या हाईकोर्ट (अनुच्छेद 226) में याचिका दायर कर सकती है, भले ही वह खुद सीधे तौर पर पीड़ित न हो (लोकस स्टैंडी के नियम में ढील दी गई है)।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

36. भारतीय संविधान के भाग-XII में वर्णित 'कर राजस्व के वितरण' (Distribution of Tax Revenues) के संदर्भ में निम्नलिखित करें में से कौन-सा कर ऐसा है जिसे केंद्र सरकार लगाती और वसूलती है, किंतु उसका संपूर्ण शुद्ध आगम (Net Proceeds) संबंधित राज्यों को ही सौंप दिया जाता है (अनुच्छेद 269)?

- (a) कृषि आय पर कर (Taxes on agricultural income)
- (b) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय पर कर
- (c) वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- (d) निगम कर (Corporation Tax)

37. 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency - अनुच्छेद 360) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सत्य है/हैं?

1. वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी घोषणा की तिथि से दो माह के भीतर अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
2. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा वापस न लिया जाए (इसके लिए बार-बार हर 6 महीने पर पुनरनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती)।
3. वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी कर्मचारियों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित) के वेतनों में कटौती का आदेश दे सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

38. भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) यह एक अखिल भारतीय निकाय (All-India Body) है जो देश में संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराता है।

- (b) यह राज्य के पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- (c) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
- (d) संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहर्ताओं (Qualifications) का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वे कानूनी, प्रशासनिक या किस पृष्ठभूमि से होने चाहिए।

39. अशोक मेहता समिति (1977), जिसने देश में पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी रिपोर्ट दी थी, ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सिफारिश की थी?

- (a) पंचायती राज व्यवस्था त्रि-स्तरीय (Three-tier) होनी चाहिए।
- (b) पंचायती राज व्यवस्था द्वि-स्तरीय (Two-tier - जिला स्तर पर जिला परिषद और नीचे मंडल पंचायत) होनी चाहिए।
- (c) पंचायतों को राजनीतिक दलों के आधार पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (d) पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के भाग-IX के तहत तुरंत संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।

40. भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को 'लघु संविधान' (Mini-Constitution) कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से संविधान के कई हिस्सों में व्यापक बदलाव किए गए थे?

- (a) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- (b) 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
- (c) 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002
- (d) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

41. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने ऐसा करने के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो (यानी कार्योत्तर विधि से संरक्षण / Ex-post facto law)।

2. किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता (यानी दोहरे खतरे से संरक्षण / Double jeopardy)।

3. किसी भी अपराध के लिए accused व्यक्ति को स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता (यानी आत्म-अभिशासन से संरक्षण / Self-incrimination)।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

42. भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) और मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित वाद (Cases) में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि "संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता"?

- (a) गोलकनाथ वाद (1967)
- (b) केशवानंद भारती वाद (1973)
- (c) मिनरवा मिल्स वाद (1980)
- (d) ए.के. गोपालन वाद (1950)

43. भारतीय संसद में 'वित्त विधेयक (श्रेणी-I) - Article 117(1)' और 'वित्त विधेयक (श्रेणी-II) - Article 117(3)' के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) सभी धन विधेयक (Money Bills) वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।
- (b) वित्त विधेयक (श्रेणी-I) को राज्यसभा में भी पुनः स्थापित किया जा सकता है।
- (c) वित्त विधेयक (श्रेणी-II) को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
- (d) वित्त विधेयक के मामले में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (Joint Sitting) नहीं बुला सकते।

44. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में 'कॉलेजियम प्रणाली' (Collegium System) की शुरुआत किस वर्ष और किस वाद के माध्यम से हुई थी?

- (a) प्रथम जज वाद (1981)

- (b) द्वितीय जज वाद (1993)
- (c) तृतीय जज वाद (1998)
- (d) केशवानंद भारती वाद (1973)

45. राज्य के राज्यपाल की 'विवेकीय शक्तियाँ' (Discretionary Powers) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति राज्यपाल के स्वविवेक के अंतर्गत आती है?

- 1. विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति का निर्णय।
- 2. मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आ जाने पर विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करना।
- 3. राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

46. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को 'अवशिष्ट शक्तियाँ' (Residuary Powers - वे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं हैं) पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान की गई है?

- (a) अनुच्छेद 245
- (b) अनुच्छेद 248
- (c) अनुच्छेद 250
- (d) अनुच्छेद 254

47. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- 1. यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- 2. इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- 3. अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी अन्य नौकरी (Employment) के पात्र नहीं होते।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

48. भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए कुल कितने कार्यकारी विषयों (Functional Items) का उल्लेख किया गया है?

- (a) 12 विषय (b) 18 विषय
(c) 29 विषय (d) 32 विषय

49. भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था?

- (a) 42वां संशोधन अधिनियम, 1976
(b) 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
(c) 61वां संशोधन अधिनियम, 1988
(d) 86वां संशोधन अधिनियम, 2002

50. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम (Sequence) निम्नलिखित में से कौन सा है?

- (a) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(b) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य
(c) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य
(d) पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य, लोकतांत्रिक

51. सूची-I (मौलिक अधिकार / अनुच्छेद) को सूची-II (संबंधित प्रावधान / अपवाद) के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची-I (अनुच्छेद/विषय)	सूची-II (विशेष प्रावधान)
a. अनुच्छेद 16(4)	1. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित आरक्षण
b. अनुच्छेद 15(5)	2. लोक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
c. अनुच्छेद 25	3. सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना
d. अनुच्छेद 30	4. अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-3, d-4 (b) a-1, b-2, c-4, d-3
(c) a-2, b-1, c-4, d-3 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

52. भारतीय संविधान के भाग-IV (DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सूक्ष्मता से विचार कीजिए:

- संविधान में मूल रूप से कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं था जो पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण की बात करता हो; इसे पूरी तरह से 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़कर अंतर्विष्ट किया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह व्यवस्था दी है कि यद्यपि DPSP सीधे न्यायोचित (Justiciable) नहीं हैं, किंतु यदि सरकार किसी कानून के जरिए DPSP को लागू करती है और वह कानून मौलिक अधिकारों (जैसे अनुच्छेद 14 या 19) का अतिक्रमण करता प्रतीत होता है, तो न्यायालय उस कानून को उचित (Reasonable) मान सकता है (अक्सर इसे 'हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन' या DPSP को प्राथमिकता का सिद्धांत कहा जाता है)।
- समान नागरिक संहिता (UCC) का उल्लेख करने वाला अनुच्छेद 44 एकमात्र ऐसा निदेशक तत्व है जिसे देश भर में आज तक पूर्ण रूप से वैधानिक और दंडात्मक रूप से लागू किया जा चुका है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

53. सूची-I (संसदीय समितियाँ) को सूची-II (सदस्य संख्या एवं प्रकृति) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (समिति)	सूची-II (विशेषता)
a. लोक लेखा समिति (PAC)	1. 30 सदस्य, सभी लोकसभा से, कोई मंत्री सदस्य नहीं
b. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)	2. 30 सदस्य (15 लोकसभा + 15 राज्यसभा), विपक्ष का नेता अध्यक्ष
c. सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU)	3. 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)
d. विशेषाधिकार समिति	4. विभिन्न सदनों के अनुसार अलग-अलग (लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10)

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4 (b) a-2, b-1, c-3, d-4
(c) a-1, b-3, c-2, d-4 (d) a-3, b-2, c-1, d-4

54. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency - अनुच्छेद 352) के उद्घोषणा और उसके प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सर्वथा असत्य (गलत) है?

- (a) राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश में या भारत के किसी विशिष्ट भाग पर की जा सकती है (यह प्रावधान 42वें संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया था)।
- (b) आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदित करने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत (Special Majority) से पारित होना चाहिए।
- (c) यदि लोकसभा का विघटन हो चुका हो और राज्यसभा ने आपातकाल के अनुमोदन का प्रस्ताव पास कर दिया हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद अपनी पहली बैठक से 30 दिनों के भीतर यदि लोकसभा प्रस्ताव पास न करे, तो आपातकाल स्वतः समाप्त हो जाता है।
- (d) राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की अनुमति हर 6 महीने पर ली जानी अनिवार्य है, और इसके लिए लोकसभा का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है।

55. सूची-I (राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद) को सूची-II (उनके विषय/कार्यों) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (विषय)
a. अनुच्छेद 155	1. राज्यपाल की नियुक्ति
b. अनुच्छेद 161	2. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति
c. अनुच्छेद 200	3. राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर अनुमति (या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना)
d. अनुच्छेद 213	4. राज्यपाल की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4
(b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-1, b-3, c-2, d-4
(d) a-4, b-3, c-1, d-2

56. उच्चतम न्यायालय की 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) और 'संविधान के मूल ढाँचे' (Basic Structure) के विकास के ऐतिहासिक कालक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- गोलकनाथ वाद (1967) में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती।
- केशवानंद भारती वाद (1973) के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह 'मूल ढाँचे' का उल्लंघन न करे।
- मिनरवा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि 'न्यायिक समीक्षा की शक्ति' स्वयं संविधान के मूल ढाँचे का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे संसद संवैधानिक संशोधन के जरिए भी समाप्त नहीं कर सकती।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

57. सूची-I (केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े आयोग/समितियाँ) को सूची-II (उनके गठन के वर्ष) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (आयोग/समिति)	सूची-II (गठन वर्ष)
a. राजन्नम समिति (Rajamannar Committee)	1. 1983
b. सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission)	2. 2007
c. पुंछी आयोग (Punchhi Commission)	3. 1969
d. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (Anandpur Sahib Resolution)	4. 1973 (या प्रादेशिक राजनीतिक दस्तावेज वर्ष 1973)

कूट:

- (a) a-3, b-1, c-2, d-4
(b) a-1, b-3, c-2, d-4
(c) a-3, b-2, c-1, d-4
(d) a-4, b-1, c-2, d-3

58. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सूक्ष्म विचार कीजिए:

1. इस संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 243-G के तहत पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने के लिए 11वीं अनुसूची के 29 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों द्वारा दी जाती है (यह अनिवार्य नहीं बल्कि राज्य की इच्छा पर है)।
2. इस अधिनियम के तहत पिछड़े वर्गों (Backward Classes) के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति सीधे तौर पर भारतीय संसद को दी गई है, राज्य विधानसभाओं को नहीं।
3. प्रत्येक राज्य में पंचायतों के चुनाव कराने के लिए 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243-K के अंतर्गत किया गया है, जिसके राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

59. सूची-I (प्रमुख संवैधानिक संशोधन) को सूची-II (उनमें किए गए ऐतिहासिक बदलावों) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संशोधन)	सूची-II (मुख्य प्रावधान)
a. 44वां संशोधन (1978)	1. संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार (अनुच्छेद 300A) बनाना
b. 52वां संशोधन (1985)	2. दलबदल विरोधी कानून (Anti-defection law) और दसवीं अनुसूची जोड़ना
c. 86वां संशोधन (2002)	3. प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बनाना
d. 91वां संशोधन (2003)	4. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना (लोकसभा/विधानसभा का अधिकतम 15%)

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4
(b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-1, b-3, c-2, d-4
(d) a-4, b-3, c-2, d-1

60. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) और निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, और निर्वाचन आयोग देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल तथा राज्यों के राज्यपाल के पदों के लिए चुनाव संपन्न कराता है।
 2. वर्ष 1993 के बाद से निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्तों के मतों का अंतर होने पर बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, किंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास वीटो पावर (Veto power) नहीं होती।
 3. निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद संविधान द्वारा उनके केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद पर दोबारा नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

61. सूची-I (रिट / Writs) को सूची-II (उनके शाब्दिक अर्थ / उद्देश्य) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (रिट)	सूची-II (शाब्दिक अर्थ / उद्देश्य)
a. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	1. हम आदेश देते हैं (We Command)
b. परमादेश (Mandamus)	2. किस अधिकार से (By what authority)
c. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)	3. शरीर को प्रस्तुत किया जाए
d. उत्प्रेषण (Certiorari)	4. पूरी तरह से प्रमाणित करना या सूचित करना

कूट:

- (a) a-1, b-3, c-2, d-4
(b) a-3, b-1, c-2, d-4
(c) a-3, b-2, c-1, d-4
(d) a-4, b-1, c-3, d-2

62. भारतीय संविधान के भाग-IV में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि DPSP के किसी भी उपबंध को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करते हैं (बशर्ते ऐसा कानून अनुच्छेद 39(b) और (c) के सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करता हो)।
2. 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़े गए नीति निदेशक तत्वों में 'समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता', 'उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी' तथा 'बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों का संरक्षण' शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

63. सूची-I (संसदीय समितियाँ) को सूची-II (उनके मुख्य कार्यक्षेत्र) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (समिति)	सूची-II (मुख्य कार्य)
a. लोक लेखा समिति (PAC)	1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की जाँच करना
b. प्रावक्लन समिति (Estimates Committee)	2. बजट में अनुमानित खर्चों में मितव्ययिता और सुधार के सुझाव देना
c. सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU)	3. सार्वजनिक उद्यमों के अहवाल और रिपोर्ट्स की समीक्षा करना
d. याचिका समिति (Committee on Petitions)	4. आम जनता द्वारा विधेयकों या मामलों पर दी गई याचिकाओं पर विचार करना

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-4, d-3
- (b) a-1, b-2, c-3, d-4
- (c) a-4, b-3, c-2, d-1
- (d) a-3, b-4, c-1, d-2

64. 'राष्ट्रीय आपातकाल' (अनुच्छेद 352) और 'राष्ट्रपति शासन' (अनुच्छेद 356) के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को कार्यकारी निर्देश (Executive Directions) देने की पूर्ण शक्ति मिल जाती है, जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका की पूरी कमान सीधे राज्यपाल के हाथ में चली जाती है।
- (b) राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति अनिवार्य है, जबकि राष्ट्रपति शासन के लिए मंत्रिमंडल की लिखित संस्तुति होना कोई संवैधानिक आवश्यकता नहीं है।
- (c) राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य विधानमंडल निलंबित या विघटित नहीं होते, वे अपने स्तर पर कानून बनाते रहते हैं (यद्यपि संसद भी बना सकती है), जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या विघटित कर दी जाती है।
- (d) राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन को बिना किसी विशेष शर्त के अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है।

65. सूची-I (राज्यपाल की शक्तियाँ) को सूची-II (संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (शक्ति / कार्य)	सूची-II (अनुच्छेद)
a. राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होना	1. अनुच्छेद 200
b. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करना	2. अनुच्छेद 161
c. विधेयकों पर अनुमति देना या राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखना	3. अनुच्छेद 154
d. राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति	4. अनुच्छेद 164

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4
- (b) a-3, b-4, c-1, d-2
- (c) a-2, b-1, c-4, d-3
- (d) a-4, b-3, c-2, d-1

66. उच्चतम न्यायालय की 'अपीलीय क्षेत्राधिकार' (Appellate Jurisdiction - अनुच्छेद 132, 133, 134) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संवैधानिक मामलों में अपील के लिए यह आवश्यक है कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामले में कानून की व्याख्या से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
2. दीवानी मामलों (Civil Cases) में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि मामले में कोई व्यापक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न निहित है और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है।
3. आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधे अपील की जा सकती है, भले ही उच्च न्यायालय ने कोई प्रमाण पत्र न दिया हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

67. सूची-I (आयोग / समिति) को सूची-II (उनके मुख्य फोकस या संस्तुतियों के क्षेत्र) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (आयोग/समिति)	सूची-II (मुख्य क्षेत्र / सिफारिश)
a. सरकारी आयोग (1983)	1. राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने और अनुच्छेद 356 के सीमित प्रयोग की संस्तुति
b. पुंछी आयोग (2007)	2. स्थानीय सरकारों और विकेंद्रीकरण के साथ-साथ केंद्र-राज्य वित्तीय संतुलन
c. वेंकटचैया आयोग (2000)	3. संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग
d. वर्मा समिति (2013)	4. आपराधिक कानूनों में संशोधन (महिला सुरक्षा और बलात्कार के मामलों पर कड़े दंड)

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4
(b) a-3, b-1, c-4, d-2
(c) a-2, b-4, c-1, d-3
(d) a-4, b-3, c-2, d-1

68. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और यदि किसी कारणवश पंचायत समय से पहले विघटित हो जाती है, तो चुनाव 6 महीने की अवधि के भीतर हो जाने चाहिए (किंतु शेष बची अवधि के लिए ही नई पंचायत गठित होगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं)।
 2. चौबीस वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं हो सकता क्योंकि न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तय की गई है।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

69. सूची-I (संवैधानिक संशोधन) को सूची-II (संबंधित वर्ष या प्रभाव) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संशोधन)	सूची-II (वर्ष / प्रावधान)
a. 42वां संशोधन	1. 1978 (संपत्ति का अधिकार समाप्त)
b. 44वां संशोधन	2. 1976 ('समाजवादी' शब्द जोड़ा गया)
c. 73वां संशोधन	3. 1992 (पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा)
d. 103वां संशोधन	4. 2019 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग - EWS आरक्षण)

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4 (b) a-2, b-1, c-3, d-4
(c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

70. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission) और मुख्य चुनाव आयुक्त की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है/हैं?

1. मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया और उनके आधार ठीक उसी प्रकार के होते हैं जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं।

2. एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों की सेवा शर्तों में ऐसा कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो उनके कार्यकाल के दौरान उनके लिए प्रतिकूल (Disadvantageous) हो।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

71. भारतीय संसद में विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया और संयुक्त बैठक (Joint Sitting - अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान संशोधन विधेयकों और धन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है।
2. यदि लोकसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर दे या ऐसे संशोधनों पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए जिन्हें लोकसभा स्वीकार न करे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं।
3. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यदि वे पद पर न हों तो लोकसभा उपाध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करेंगे—राज्यसभा के उपसभापति को इसकी अध्यक्षता करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

72. सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (संबंधित मौलिक अधिकार / स्वतंत्रता) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (प्रावधान)
a. अनुच्छेद 19(1)(a)	1. शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता
b. अनुच्छेद 19(1)(b)	2. भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
c. अनुच्छेद 19(1)(d)	3. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Speech & Expression)
d. अनुच्छेद 19(1)(e)	4. भारत के राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण (Movement) की स्वतंत्रता

कूट:

- (a) a-3, b-1, c-4, d-2
(b) a-1, b-3, c-2, d-4
(c) a-4, b-2, c-1, d-3
(d) a-2, b-4, c-3, d-1

73. भारतीय संविधान के भाग-IV में वर्णित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) और उनके वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में DPSP को स्पष्ट रूप से समाजवादी, गांधीवादी या उदारवादी-बौद्धिक श्रेणियों में विभाजित नहीं किया गया है, बल्कि यह वर्गीकरण केवल उनकी वैचारिक प्रकृति को समझने के लिए विद्वानों द्वारा किया गया है।
 2. 'अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि' से संबंधित अनुच्छेद 51 का संबंध उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों से है, न कि समाजवादी या गांधीवादी सिद्धांतों से।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

74. सूची-I (राज्यपाल की विधायी व वित्तीय शक्तियाँ) को सूची-II (संबंधित अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (कार्य / शक्ति)	सूची-II (अनुच्छेद)
a. राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटन करना	1. अनुच्छेद 207
b. राज्य के वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) को प्रस्तुत करवाना	2. अनुच्छेद 174
c. वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष सिफारिश (पूर्व अनुमति)	3. अनुच्छेद 202
d. विधानपरिषद में एक-तिहाई सदस्यों का मनोनयन (कला, साहित्य, विज्ञान आदि से)	4. अनुच्छेद 171(3)(e)

कूट:

- (a) a-2, b-3, c-1, d-4 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-3, b-4, c-2, d-1 (d) a-4, b-1, c-2, d-3

75. 'राष्ट्रीय आपातकाल' (अनुच्छेद 352) के दौरान केंद्र-राज्य विधायी संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है (असत्य है)?

- (a) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची (State List) में शामिल किसी भी विषय पर पूरे देश या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
 (b) आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
 (c) संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल समाप्त होने के ठीक 6 महीने बाद निष्प्रभावी (Inactive) हो जाता है।
 (d) यदि संसद सत्र में न हो, तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश (Ordinance) प्रख्यापित कर सकते हैं।

76. सूची-I (सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद) को सूची-II (उनके विषय) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (विषय / क्षेत्राधिकार)
a. अनुच्छेद 129	1. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होना
b. अनुच्छेद 136	2. अपील के लिए विशेष अनुमति (Special Leave Petition - SLP)
c. अनुच्छेद 141	3. सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी (Binding) होना
d. अनुच्छेद 143	4. राष्ट्रपति की सलाहकार अधिकारिता (Advisory Jurisdiction)

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4 (b) a-4, b-3, c-2, d-1
 (c) a-2, b-4, c-1, d-3 (d) a-3, b-1, c-4, d-2

77. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 (नगरपालिकाओं से संबंधित) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - अनुच्छेद 243-ZD) और 'महानगर योजना समिति' (Metropolitan Planning Committee - अनुच्छेद 243-ZE) के गठन का अनिवार्य प्रावधान किया गया है।

2. जिला योजना समिति का मुख्य कार्य जिले के लिए विकास योजनाएं तैयार करना है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की योजनाओं का समन्वय किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

78. भारतीय संविधान के भाग-XII में वर्णित केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों (Financial Relations) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीएसटी (GST) परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं।
 2. संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत संघ या राज्य सरकारें अपनी राजस्व आय से किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वित्तीय अनुदान (Grants) दे सकती हैं, भले ही वह उनके विधायी अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय क्यों न हो (यही प्रावधान देश में 'विवेकाधीन अनुदानों' या राजनीतिक योजनाओं के वित्तपोषण का आधार बनता है)।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

79. सूची-I (संशोधन अधिनियम) को सूची-II (संबंधित प्रमुख प्रावधान) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संशोधन)	सूची-II (मुख्य प्रावधान)
a. 52वां संशोधन (1985)	1. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना
b. 61वां संशोधन (1988)	2. दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची)
c. 91वां संशोधन (2003)	3. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना (बाद में रद्द)
d. 99वां संशोधन (2014)	4. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना और दलबदल के आधार पर मंत्री बनने पर रोक

- कूट: (a) a-2, b-1, c-4, d-3 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
 (c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

80. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

1. संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (2) में यह उपबंध है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितनी संख्या राष्ट्रपति समय-समय पर तय करें।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच वेतन, भत्ते और अन्य सेवा-शर्तों के मामले में कोई अंतर नहीं होता—तीनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

81. भारतीय संसद में 'विशेष बहुमत' (Special Majority) के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए 'संसद के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत' आवश्यक होता है।
2. राष्ट्रपति पर महाभियोग (Impeachment - अनुच्छेद 61) चलाने के लिए 'संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई बहुमत' अनिवार्य होता है।
3. राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए 'संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत' आवश्यक होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

82. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A (शिक्षा का अधिकार) और 86वें संविधान संशोधन (2002) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है (असत्य है)?

- (a) इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने को मौलिक अधिकार बनाया गया है।
- (b) इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग-IV में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु को बदला गया और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल (ECC) का प्रावधान जोड़ा गया।
- (c) इस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों (Fundamental Duties) के तहत एक नया कर्तव्य (11वां कर्तव्य) जोड़ा गया जो माता-पिता या संरक्षक का यह दायित्व तय करता है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।
- (d) इस मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act)' वर्ष 2002 में ही पारित कर दिया था जो उसी वर्ष लागू हो गया था।

83. सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (नीति निर्देशक तत्वों के विषय) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (विषय)
a. अनुच्छेद 39(A)	1. ग्राम पंचायतों का संगठन
b. अनुच्छेद 40	2. समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता
c. अनुच्छेद 43	3. कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन
d. अनुच्छेद 47	4. पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-3, d-4
- (b) a-1, b-2, c-3, d-4
- (c) a-3, b-4, c-2, d-1
- (d) a-4, b-3, c-1, d-2

84. राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालय के 'कुलपति' (Chancellor) के रूप में कार्य करने की वैधानिक शक्ति प्राप्त होती है (सामान्यतः राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल ही होते हैं)।
2. राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं (अनुच्छेद 217)।
3. राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति होती है, किंतु उन्हें हटाने का अधिकार केवल और केवल 'भारत के राष्ट्रपति' के पास होता है (राज्यपाल उन्हें नहीं हटा सकते)।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

85. भारतीय संविधान के भाग-XVIII में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) आपातकाल की उद्घोषणा को केवल 'सुप्रीम कोर्ट' द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है, उच्च न्यायालयों (High Courts) का इस पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
- (b) 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर पारित होना चाहिए।
- (c) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के दौरान राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित सभी धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होता है।
- (d) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की अवधि को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।

86. उच्चतम न्यायालय की 'अवमानना की शक्ति'

(Contempt of Court - अनुच्छेद 129 और 142) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में 'न्यायालय की अवमानना' (Civil और Criminal Contempt दोनों) को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
2. संसद को यह विधायी शक्ति प्राप्त है कि वह न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून बना सकती है (इसी के तहत 'न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971' बनाया गया था)।
3. उच्च न्यायालयों के पास भी अपने और अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति अनुच्छेद 215 के तहत होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

87. 73वें संविधान संशोधन (1992) के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है/हैं?

1. पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) पर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही कराए जाने का संवैधानिक प्रावधान अनिवार्य किया गया है।
 2. पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।
 3. राज्य में पंचायतों के चुनाव कराने और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की होती है।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 2
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

88. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई सूचियों (Lists) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा विषय 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) का हिस्सा है?

- (a) जन स्वास्थ्य और स्वच्छता (Public Health and Sanitation)
- (b) पुलिस, जेल और स्थानीय शासन
- (c) आर्थिक और सामाजिक योजना (Economic and Social Planning)
- (d) कृषि और भूमि राजस्व (Agriculture & Land Revenue)

89. सूची-I (संवैधानिक निकाय / आयोग) को सूची-II (संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (निकाय)	सूची-II (अनुच्छेद)
a. भारत का निर्वाचन आयोग	1. अनुच्छेद 315
b. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	2. अनुच्छेद 324
c. वित्त आयोग	3. अनुच्छेद 338
d. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)	4. अनुच्छेद 280

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-4, d-3 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

90. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है (42वें संशोधन द्वारा)। इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस क्रम में नए शब्द जोड़े गए थे?

- (a) पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता
(b) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता
(c) अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष
(d) समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष

91. भारतीय संसद में 'अवशेष शक्तियाँ' (Residuary Powers) और विधायी सूचियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में 97 (वर्तमान में लगभग 100), राज्य सूची में 66 (वर्तमान में लगभग 61) और समवर्ती सूची में 47 (वर्तमान में लगभग 52) विषय मूल रूप से शामिल किए गए थे।
- संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, वे सभी विषय जो किसी भी सूची (संघ, राज्य या समवर्ती) में शामिल नहीं हैं (यानी अवशिष्ट शक्तियाँ), उन पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल और केवल 'संसद' के पास होती है।
- समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि केंद्र (संसद) और राज्य (विधानमंडल) दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराव उत्पन्न हो जाए, तो राज्य का कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा, बशर्ते उसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

92. सूची-I (मौलिक अधिकारों से जुड़े वाद / Case) को सूची-II (उनके मुख्य न्यायिक सिद्धांत या निर्णय) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (वाद / Case)	सूची-II (मुख्य निर्णय / सिद्धांत)
a. ए.के. गोपालन वाद (1950)	1. संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती (गोलकनाथ केस)
b. गोलकनाथ वाद (1967)	2. विधि की सम्यक प्रक्रिया (Due Process of Law) का दायरा और अनुच्छेद 21 का व्यापक विस्तार (मेनका गांधी केस)
c. केशवानंद भारती वाद (1973)	3. निवारक निरोध के मामले में 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) की संकीर्ण व्याख्या
d. मेनका गांधी वाद (1978)	4. संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure) सिद्धांत

कूट:

- (a) a-3, b-1, c-4, d-2 (b) a-1, b-3, c-2, d-4
(c) a-4, b-2, c-1, d-3 (d) a-2, b-4, c-3, d-1

93. भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य नहीं है (असत्य है)?

- (a) ये निर्देश देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं।
(b) इन्हें देश के किसी भी न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू (Enforceable) नहीं कराया जा सकता।
(c) संविधान निर्माताओं ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया था, जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था।
(d) यदि कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है, तो नागरिक उनके खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

94. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल (Electoral College - अनुच्छेद 54) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और मनोनीत—दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं।
 2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली तथा पुदुचेरी (तथा जम्मू-कश्मीर) केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं।
 3. राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों की अंतिम जाँच और निर्णय केवल 'उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court) द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम होता है (अनुच्छेद 71)।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

95. उच्चतम न्यायालय की 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record - अनुच्छेद 129) की शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है?

1. सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय, अभिलेख और कार्यवाही स्थायी रूप से संरक्षित रखे जाते हैं और देश के अन्य सभी न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं (इनकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता)।
2. सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए किसी भी व्यक्ति को साधारण कारावास या जुर्माने से दंडित करने की अखिन्न शक्ति प्राप्त होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

96. सूची-I (आपातकाल के प्रकार) को सूची-II (संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (आपातकाल)	सूची-II (अनुच्छेद)
------------------	--------------------

a. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)	1. अनुच्छेद 356
b. राष्ट्रपति शासन (President's Rule / State Emergency)	2. अनुच्छेद 360
c. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)	3. अनुच्छेद 352

कूट:

- (a) a-3, b-1, c-2
- (b) a-1, b-2, c-3
- (c) a-2, b-3, c-1
- (d) a-3, b-2, c-1

97. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है/हैं?

1. इस संशोधन के जरिए संविधान में नया भाग-IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए कुल 29 विषयों का प्रावधान किया गया।
 2. इस अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कम से कम एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है, और कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% भी किया है।
- नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

98. भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (a) संविधान संशोधन विधेयक केवल राज्यों की विधानसभाओं में ही पेश किया जा सकता है।
- (b) इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है।
- (c) इस विधेयक को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में 'विशेष बहुमत' (कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने का 2/3 बहुमत) होना अनिवार्य है, और दोनों सदनों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
- (d) इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है, और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

99. भारत के 'वित्त आयोग' (Finance Commission - अनुच्छेद 280) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-judicial body) है जिसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर या आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

2. वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी योग्यताएँ संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

3. वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के लिए सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांत तय करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

100. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है और इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा वाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 'प्रस्तावना संविधान का भाग है'?

- (a) दो बार; बेरूबारी यूनियन वाद (1960)
(b) कभी नहीं; गोपालन वाद (1950)
(c) केवल एक बार (42वें संशोधन द्वारा, 1976); केशवानंद भारती वाद (1973)
(d) तीन बार; मिनरवा मिल्स वाद (1980)

101. भारतीय संसद में 'धन विधेयक' (Money Bill - अनुच्छेद 110) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) का होता है, और उनका यह निर्णय किसी भी न्यायालय में या संसद के किसी भी सदन में चुनौती नहीं दिया जा सकता।

2. धन विधेयक को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य होती है, और जब यह विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने की संवैधानिक शक्ति नहीं होती।

3. राज्यसभा को धन विधेयक को संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है, किंतु वह अधिकतम 30 दिनों की अवधि तक इसे अपने पास रोक सकती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

102. सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (संबंधित मौलिक अधिकार / स्वतंत्रता) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (प्रावधान)
a. अनुच्छेद 17	1. उपाधियों का अंत (Abolition of Titles)
b. अनुच्छेद 18	2. अस्पृश्यता का अंत (Untouchability)
c. अनुच्छेद 23	3. कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध
d. अनुच्छेद 24	4. मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार (Human Trafficking & Forced Labour)

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-4, d-3
(b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-3, b-4, c-1, d-2
(d) a-4, b-3, c-2, d-1

103. भारतीय संविधान के भाग-IV में वर्णित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि DPSP का उद्देश्य देश में 'राजनीतिक लोकतंत्र' (Political Democracy) की स्थापना करना है, जबकि मौलिक अधिकार 'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र' स्थापित करते हैं।

2. सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे मिनरवा मिल्स वाद, 1980) में यह प्रतिपादित किया है कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का एक अनिवार्य हिस्सा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

104. राज्य के राज्यपाल के रूप में 'क्षमादान की शक्ति' (Pardoning Power - अनुच्छेद 161) और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72) के बीच निम्नलिखित में से क्या अंतर है?

1. राष्ट्रपति 'मृत्युदंड' (Death Sentence) की सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड को पूरी तरह क्षमा करने (Pardon) की संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।
2. राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय (Martial Law) द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा के मामले में ऐसा नहीं कर सकते।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

105. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि के संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता) के अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते।
2. जब राष्ट्रीय आपातकाल 'युद्ध या बाह्य आक्रमण' के आधार पर लगाया जाता है, तभी अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त छह स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित होती हैं; यदि आपातकाल 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर लगा हो, तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

106. सूची-I (सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े न्यायिक सिद्धांत / प्रावधान) को सूची-II (संबंधित अनुच्छेद या अवधारणा) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (सिद्धांत / प्रावधान)	सूची-II (अनुच्छेद / विवरण)
a. मूल अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)	1. अनुच्छेद 143 (राष्ट्रपति की सलाह)
b. अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)	2. अनुच्छेद 131 (केंद्र-राज्य या अंतर-राज्य विवाद)

c. सलाहकार क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction)	3. अनुच्छेद 132, 133, 134 (संवैधानिक, दीवानी व आपराधिक अपील)
d. कोर्ट ऑफ रिपोर्ट्स (अभिलेख न्यायालय)	4. अनुच्छेद 129 (निर्णयों का अभिलेखीकरण और अवमानना पर दंड)

कूट:

- (a) a-2, b-3, c-1, d-4 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-4, b-3, c-2, d-1 (d) a-3, b-1, c-4, d-2

107. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत 'ग्राम सभा' (Gram Sabha - अनुच्छेद 243A) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का एकमात्र ऐसा अंग है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र (Direct Democracy) का प्रतीक है, क्योंकि इसमें गाँव के वे सभी लोग शामिल होते हैं जो उस ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं।
2. ग्राम सभा की बैठकें और उसके अधिकार राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं, और संविधान ने इसके कार्यों को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया है बल्कि राज्यों पर छोड़ा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

108. भारतीय संविधान के भाग-XII के अंतर्गत 'वित्त आयोग' (Finance Commission - अनुच्छेद 280) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर पहले भी किया जा सकता है।
(b) वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
(c) वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होती हैं, और केंद्र सरकार उन्हें मानने से इंकार नहीं कर सकती।
(d) यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (Grants-in-aid) के सिद्धांत तय करता है।

109. भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया (अनुच्छेद 368) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के फेडरल प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, सातवीं अनुसूची के विषय आदि) में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ-साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन (Ratification) आवश्यक है।

2. संविधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) में संशोधन करने के लिए केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की कोई आवश्यकता नहीं होती।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

110. सूची-I (संवैधानिक व सांविधिक निकाय) को सूची-II (संबंधित अनुच्छेद या स्थापना वर्ष) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (निकाय)	सूची-II (अनुच्छेद / वर्ष)
a. भारत का निर्वाचन आयोग	1. अनुच्छेद 324
b. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	2. अनुच्छेद 315
c. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)	3. अनुच्छेद 148
d. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC)	4. वर्ष 1993 (सांविधिक निकाय)

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4 (b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

111. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत प्रदत्त 'संसदीय विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान ने संसद के विशेषाधिकारों को देश के सामान्य कानूनों से ऊपर रखा है, और यदि सदन के भीतर किसी विशेषाधिकार का हनन होता है, तो सदन स्वयं अपने आंतरिक मामलों के तहत दंड देने का अधिकार (Privilege power) रखता है।

2. किसी भी सांसद को संसद के सत्र के दौरान या सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व और सत्र समाप्त होने के 40 दिन पश्चात किसी भी प्रकार के 'दीवानी मामले' (Civil Cases) में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

3. संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत सदन के भीतर सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए मत के संबंध में देश की किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

112. सूची-I (मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद) को सूची-II (उनके विशिष्ट प्रावधानों) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (प्रावधान)
a. अनुच्छेद 20(1)	1. दोहरे खतरे से संरक्षण (Protection against double jeopardy)
b. अनुच्छेद 20(2)	2. आत्म-अभिशासन से संरक्षण (Protection against self-incrimination)
c. अनुच्छेद 20(3)	3. कार्योत्तर विधि से संरक्षण (Ex-post facto law)
d. अनुच्छेद 21	4. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of life and personal liberty)

कूट:

- (a) a-3, b-1, c-2, d-4 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-4, b-3, c-1, d-2 (d) a-2, b-4, c-3, d-1

113. भारतीय संविधान के भाग-IV में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में संशोधन करके जोड़े गए अनुच्छेद 39A के तहत देश में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 'कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' पारित किया था।

2. सहकारी समितियों के गठन और उनके स्वैच्छिक कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित नीति निदेशक तत्व (अनुच्छेद 43B) को मूल संविधान में ही शामिल किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

114. भारत के राष्ट्रपति की 'वीटो शक्तियों' (Veto Powers - अनुच्छेद 111) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) राष्ट्रपति के पास 'अत्यंतिक वीटो' (Absolute Veto) की शक्ति होती है जिसके तहत वे किसी गैर-सरकारी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं।
- (b) राष्ट्रपति के पास 'निलंबनकारी वीटो' (Suspensive Veto) होता है जिसके जरिए वे किसी साधारण विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं (किंतु यदि संसद उसे दोबारा बिना बदलाव या संशोधन के पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी)।
- (c) भारतीय राष्ट्रपति के पास 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto) की शक्ति होती है, जिसका प्रयोग उन्होंने वर्ष 1986 में 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पर ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया था।
- (d) भारतीय राष्ट्रपति के पास 'विशेष वीटो' (Qualified Veto) की शक्ति भी प्राप्त है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर संसद के उच्च बहुमत द्वारा ही खारिज किया जा सकता है।

115. उच्चतम न्यायालय की 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 137 और अनुच्छेद 13 के विभिन्न खंडों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
2. न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना और विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों या आदेशों को असंवैधानिक घोषित करना है जो मौलिक अधिकारों या संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।
- उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

116. सूची-I (आपातकाल के दौरान होने वाले प्रभाव) को सूची-II (संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (प्रभाव / प्रावधान)	सूची-II (अनुच्छेद)

a. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा	1. अनुच्छेद 358
b. अनुच्छेद 19 के अधिकारों का स्वतः निलंबन	2. अनुच्छेद 352
c. आपातकाल के दौरान भाग-III के अन्य अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)	3. अनुच्छेद 356
d. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन	4. अनुच्छेद 359

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-4, d-3 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

117. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के वित्त और लेखा-जोखा के परीक्षण के लिए किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है?

- (a) राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - अनुच्छेद 243-I)
(b) भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)
(c) राष्ट्रीय विकास परिषद
(d) जिला योजना समिति

118. भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान की सातवीं अनुसूची की 'संघ सूची' में मूल रूप से 97 विषय थे, जो अब बढ़कर लगभग 100 हो गए हैं, और इन पर केवल संसद कानून बना सकती है।
2. 'राज्य सूची' में मूल रूप से 66 विषय थे, जिनमें से कुछ विषयों (जैसे शिक्षा, वन, वन्यजीव, माप-तोल) को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे राज्य सूची में अब लगभग 61 विषय बचे हैं।
3. समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, जो अब बढ़कर लगभग 52 हो गए हैं, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में राज्य का कानून मान्य होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

119. सूची-I (संवैधानिक संशोधन) को सूची-II (संबंधित प्रमुख परिवर्तन) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संशोधन)	सूची-II (मुख्य प्रावधान)
a. 42वां संशोधन (1976)	1. संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना (अनुच्छेद 300A)
b. 44वां संशोधन (1978)	2. प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़ना
c. 86वां संशोधन (2002)	3. मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करना
d. 61वां संशोधन (1988)	4. शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21A) बनाना

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-4, d-3
- (b) a-1, b-2, c-3, d-4
- (c) a-3, b-4, c-1, d-2
- (d) a-4, b-3, c-2, d-1

120. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है, जो संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
- निर्वाचन आयोग के पास चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू करने की वैधानिक शक्ति होती है, और यह आचार संहिता सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 324 से ही अपनी शक्ति प्राप्त करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, और न ही 2

121. भारतीय संसद की वित्तीय और विभागीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 'लोक लेखा समिति' (PAC) के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और परंपरा के अनुसार यह अध्यक्ष हमेशा 'सत्तारूढ़ दल' (Ruling Party) से ही चुना जाता है।
 - संसद की 'विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ' (Departmental Standing Committees), जिनकी कुल संख्या 24 है, मंत्रालयों के अनुदान मांगों और वार्षिक प्रतिवेदनों की विस्तृत जाँच करती हैं।
 - प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) में कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

122. सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (संबंधित स्वतंत्रता या अधिकार) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (प्रावधान)
a. अनुच्छेद 25	1. धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
b. अनुच्छेद 26	2. अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
c. अनुच्छेद 27	3. किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता
d. अनुच्छेद 28	4. कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-3, d-4
- (b) a-1, b-2, c-4, d-3
- (c) a-3, b-4, c-1, d-2
- (d) a-4, b-3, c-2, d-1

123. भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं है (कौन सा गलत है)?

- (a) अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायतों का संगठन) - गांधीवादी सिद्धांत
- (b) अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) - उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत
- (c) अनुच्छेद 48A (पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा) - समाजवादी सिद्धांत
- (d) अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण) - प्रशासनिक / उदारवादी सिद्धांत

124. भारत के राष्ट्रपति के 'अध्यादेश जारी करने की शक्ति' (Ordinance Making Power - अनुच्छेद 123) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रपति यह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सत्रों में न हों (या कोई एक सत्र में न हो)।
 2. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही कानूनी शक्ति और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का होता है, और यह संसद के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है।
 3. राष्ट्रपति का यह अध्यादेश जारी करने का विवेक पूर्णतः स्वतंत्र और असीम होता है, और इसकी न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

125. उच्चतम न्यायालय की 'जनहित याचिका' (PIL) और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा का विकास अमेरिका की न्याय प्रणाली से प्रेरित होकर भारत में हुआ, जिसे 'सोशल एक्शन लिटिगेशन' (SAL) भी कहा जाता है।
- (b) PIL के मामले में 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi - यानी केवल पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है) के पारंपरिक नियम में ढील दी गई है, जिससे कोई भी सार्वजनिक हितैषी व्यक्ति या संस्था अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।

(c) जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) में ही दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालयों (High Courts) में PIL दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(d) न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर को भारत में PIL का अग्रदूत माना जाता है।

126. सूची-I (आपातकाल के प्रकार) को सूची-II (उनके संवैधानिक अनुमोदन और अधिकतम अवधि के प्रावधान) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (आपातकाल)	सूची-II (मुख्य प्रावधान / अवधि)
a. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)	1. संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन; अधिकतम 3 वर्ष तक विस्तार संभव
b. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)	2. संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर अनुमोदन; अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है
c. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)	3. संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन; एक बार अनुमोदित होने पर अनिश्चित काल तक प्रभावी जब तक वापस न लिया जाए

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-3
- (b) a-1, b-2, c-3
- (c) a-3, b-1, c-2
- (d) a-2, b-3, c-1

127. 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992) के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन-से नए भाग और अनुसूचियाँ जोड़ी गईं?

- (a) भाग IX और IX-A; तथा 10वीं और 11वीं अनुसूची
- (b) भाग IX और IX-A; तथा 11वीं और 12वीं अनुसूची
- (c) भाग VIII और IX; तथा 11वीं और 12वीं अनुसूची
- (d) भाग IX और X; तथा 9वीं और 10वीं अनुसूची

128. भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित 'सरकारिया आयोग' (Sarkaria Commission - 1983) ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सिफारिश की थी?

1. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग एक 'अंतिम उपाय' (Ultima ratio) के रूप में किया जाना चाहिए, जब अन्य सभी विकल्प विफल हो जाएं।
 2. राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए जो राज्य की राजनीति से तटस्थ और सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो।
 3. अंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council - अनुच्छेद 263) का स्थायी रूप से यथाशीघ्र गठन किया जाना चाहिए।
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

129. सूची-I (संवैधानिक संशोधन) को सूची-II (उनसे जुड़े ऐतिहासिक प्रभाव) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संशोधन)	सूची-II (मुख्य प्रावधान)
a. 38वां संशोधन (1975)	1. राष्ट्रपति की आपातकाल घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना
b. 42वां संशोधन (1976)	2. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष करना
c. 44वां संशोधन (1978)	3. आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द जोड़ना
d. 52वां संशोधन (1985)	4. दलबदल विरोधी कानून और दसवीं अनुसूची जोड़ना

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4 (b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

130. भारत के 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त' (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की होती है, किंतु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए

मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश अनिवार्य होती है (और राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं)।

2. यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच किसी निर्णय को लेकर मतभेद हो जाता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास 'वीटो पावर' (Veto Power) होती है जिससे उनका निर्णय अंतिम माना जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

131. भारतीय संसद में 'संसदीय विशेषाधिकार' (Parliamentary Privileges - अनुच्छेद 105) के उल्लंघन और 'सदन की अवमानना' (Breach of Privilege / Contempt) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यदि कोई व्यक्ति या सांसद सदन के किसी विशेषाधिकार का हनन करता है या सदन की अवमानना करता है, तो संसद के दोनों सदनों को अपनी आंतरिक सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए बिना किसी बाहरी अदालत की अनुमति के दोषी व्यक्ति को तुरंत दंडित करने (कारावास या ताड़ना) की शक्ति प्राप्त होती है।
2. भारतीय संसद के ये विशेषाधिकार पूरी तरह से लिखित और संहिताबद्ध (Codified) हैं, और संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (3) में इनकी पूरी सूची स्पष्ट रूप से एक अलग अधिनियम के रूप में दर्ज है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

132. सूची-I (मौलिक अधिकार से जुड़े वाद / Case) को सूची-II (उनके ऐतिहासिक महत्व) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (वाद)	सूची-II (महत्वपूर्ण विषय)
a. Champakam Dorairajan Case (1951)	1. निजता का अधिकार (Right to Privacy) एक मौलिक अधिकार है
b. ADM Jabalpur Case (1976)	2. शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सांप्रदायिक अधिनिर्णय (Communal G.O.) का विरोध
c. Indra Sawhney Case (1992)	3. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के तहत भी

	अदालत जाने के अधिकार का निलंबन (हैबियस कॉर्पस केस)
d. K.S. Puttaswamy Case (2017)	4. मंडल आयोग के फैसले और क्रीमी लेयर (Creamy Layer) की अवधारणा

कूट:

- (a) a-2, b-3, c-4, d-1 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-4, b-3, c-2, d-1 (d) a-3, b-4, c-1, d-2

133. भारतीय संविधान के भाग-IV में वर्णित नीति निदेशक तत्वों (DPSP) और उनके न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो देश के संसाधनों के विकेंद्रीकरण और आर्थिक समानता (अनुच्छेद 39b और 39c) को बढ़ावा देता है, तो उस कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर अदालत द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 31C)।
- 'समान नागरिक संहिता' (UCC - अनुच्छेद 44) को लागू करने की संवैधानिक जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ी गई है, और यह एक न्यायोचित (Justiciable) अधिकार है जिसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, और न ही 2

134. भारत के राष्ट्रपति के 'महाभियोग की प्रक्रिया' (Impeachment - अनुच्छेद 61) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रस्तुत किया जा सकता है।
(b) इस प्रस्ताव को लाने से कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को एक लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए जिस पर उस सदन के एक-चौथाई (1/4th) सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
(c) महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई

बहुमत (Special Majority) से पारित किया जाना अनिवार्य है।

(d) राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के केवल 'निर्वाचित' सदस्य ही भाग लेते हैं, 'मनोनीत' (Nominated) सदस्यों को इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता।

135. उच्चतम न्यायालय के 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) और 'नौवीं अनुसूची' (Ninth Schedule) के अंतःसंबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद भारती वाद का दिन) से पहले नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक 'आई.आर. कोएलो वाद (2007)' के निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में जोड़े गए किसी भी ऐसे कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है जो संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का उल्लंघन करता हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

136. सूची-I (आपातकाल के प्रकार) को सूची-II (संबंधित प्रभावों या संशोधनों) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (आपातकाल)	सूची-II (मुख्य प्रावधान / संशोधन)
a. 44वां संविधान संशोधन (1978)	1. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पूर्ण प्रतिबंध
b. 42वां संविधान संशोधन (1976)	2. राष्ट्रीय आपातकाल को देश के किसी विशेष हिस्से (भाग) तक सीमित करने का प्रावधान
c. मिनरवा मिल्स वाद (1980)	3. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की न्यायिक समीक्षा को वैध ठहराया गया
d. एस.आर. बोम्मई वाद (1994)	4. राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर कड़े प्रतिबंध और धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना गया

कूट:

- (a) a-2, b-1, c-3, d-4 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-3, b-4, c-1, d-2 (d) a-4, b-3, c-2, d-1

137. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992

(नगरपालिकाओं से संबंधित) के अंतर्गत नगरपालिकाओं के कितने प्रकार (Types) और वित्तीय संसाधनों के परीक्षण के लिए किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है?

- (a) दो प्रकार की नगरपालिकाएँ; और केंद्रीय वित्त आयोग
(b) तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम); और राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)
(c) चार प्रकार की नगरपालिकाएँ; और योजना आयोग
(d) तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ; और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)

138. भारतीय संविधान के भाग-XI के अंतर्गत 'प्रशासनिक संबंधों' (Administrative Relations - अनुच्छेद 256-263) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संविधान का अनुच्छेद 256 यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश (Executive Directions) दे सकती है ताकि राज्यों की कार्यपालिका केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न उत्पन्न करे (अनुच्छेद 257)।
- यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने से इनकार कर देता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकते हैं कि उस राज्य में 'संवैधानिक तंत्र विफल' हो गया है और वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

139. सूची-I (संवैधानिक संशोधन) को सूची-II (संबंधित वर्ष और प्रभाव) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संशोधन)	सूची-II (वर्ष / प्रावधान)
a. 91वां संशोधन (2003)	1. सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण (अनुच्छेद 19 और 43B)
b. 97वां संशोधन (2011)	2. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन (अमान्य घोषित)

c. 99वां संशोधन (2014)	3. मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना (अधिकतम 15%)
d. 103वां संशोधन (2019)	4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण

कूट:

- (a) a-3, b-1, c-2, d-4 (b) a-1, b-2, c-3, d-4
(c) a-2, b-3, c-4, d-1 (d) a-4, b-1, c-2, d-3

140. भारत के 'महान्यायवादी' (Attorney General of India - अनुच्छेद 76) और 'महाधिवक्ता' (Advocate General - अनुच्छेद 165) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- महान्यायवादी देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी (Chief Law Officer) होते हैं, जिनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के समान होनी चाहिए, और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं।
- महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु उन्हें संसद की बैठकों में 'मतदान करने' (Right to Vote) का कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- राज्य के महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165) की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और उनकी योग्यता उच्च न्यायालय (High Court) के न्यायाधीश बनने के योग्य होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

141. भारतीय संसद में 'संसदीय समितियों' और उनकी कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- 'लोक लेखा समिति' (PAC) का मुख्य दायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनों (Audit Reports) की जाँच करना होता है।
- प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, जो न केवल बजट अनुमानों की जाँच करती है बल्कि प्रशासन में मितव्ययिता और दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के सुझाव भी देती है।
- 'सार्वजनिक उपक्रम समिति' (COPU) के सभी 22 सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

142. सूची-I (अनुच्छेद) को सूची-II (संबंधित मौलिक अधिकार / संरक्षण) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (अनुच्छेद)	सूची-II (प्रावधान)
a. अनुच्छेद 15	1. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
b. अनुच्छेद 16	2. लोक रोजगार के विषयों में अवसर की समानता
c. अनुच्छेद 19	3. वाक्, अभिव्यक्ति, सम्मेलन और संचरण की स्वतंत्रता
d. अनुच्छेद 21	4. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4
(b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-3, b-4, c-1, d-2
(d) a-4, b-3, c-2, d-1

143. भारतीय संविधान के भाग-IV में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे (अनुच्छेद 38)।

2. 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (Equal pay for equal work) का सिद्धांत एक संवैधानिक और नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो मूल रूप से अनुच्छेद 39(d) में वर्णित है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

144. भारत के राष्ट्रपति के 'निर्वाचन मंडल' (Electoral College - अनुच्छेद 54) और 'महाभियोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन असत्य है (गलत है)?

- (a) राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल 'निर्वाचित' सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं।
(b) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेशों की

विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

(c) राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ 'मनोनीत' सदस्य भी भाग लेते हैं।

(d) राज्यों की विधानपरिषद (Legislative Councils) के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग—दोनों प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

145. उच्चतम न्यायालय की 'न्यायिक सक्रियता' (Judicial Activism) और जनहित याचिका (PIL) के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य अदालतों द्वारा पारंपरिक रूप से केवल मुकदमों के फैसले देने की भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति सक्रिय रूप से निर्देशित करने या नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करने से है।

2. जनहित याचिका (PIL) ने न्यायपालिका के द्वार समाज के गरीब, शोषित और वंचित वर्गों के लिए खोल दिए हैं, जिससे 'लोकस स्टैंडी' के कड़े नियम शिथिल हुए हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, और न ही 2

146. सूची-I (आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव) को सूची-II (संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (प्रावधान)	सूची-II (अनुच्छेद)
a. राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का आधार (युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह)	1. अनुच्छेद 352
b. अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता का स्वतः निलंबन	2. अनुच्छेद 358
c. आपातकाल के दौरान भाग-III के अन्य अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन (राष्ट्रपति के आदेश द्वारा)	3. अनुच्छेद 359
d. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन)	4. अनुच्छेद 356

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4 (b) a-4, b-3, c-2, d-1
(c) a-2, b-1, c-4, d-3 (d) a-3, b-4, c-1, d-2

147. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है?

- (a) केवल जिला स्तर पर 33% आरक्षण
(b) पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) पर कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33%) आरक्षण, जिसमें एससी/एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं
(c) सभी स्तरों पर ठीक 50% आरक्षण जो पूरे देश में अनिवार्य है
(d) महिलाओं के लिए कोई संवैधानिक आरक्षण नहीं है, यह केवल राज्यों की मर्जी पर है

148. भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'वित्तीय संबंधों' और करों के आरोपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संविधान की सातवीं अनुसूची की 'संघ सूची' में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर कर लगाने का अनन्य अधिकार संसद के पास है (जैसे निगम कर, सीमा शुल्क, आयकर आदि)।
- 'राज्य सूची' के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कर लगाने की शक्ति राज्य विधानमंडलों के पास होती है (जैसे भू-राजस्व, कृषि आय पर कर, स्टांप शुल्क आदि)।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST - अनुच्छेद 279A) के आने के बाद से केंद्र और राज्य दोनों को समवर्ती रूप से जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, और इसके लिए संसद या राज्य अलग-अलग अपने स्तर पर कर दरें तय कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

149. सूची-I (संवैधानिक निकाय / आयोग) को सूची-II (संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद) के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची-I (निकाय)	सूची-II (अनुच्छेद)
a. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)	1. अनुच्छेद 148
b. भारत का महान्यायवादी (Attorney General)	2. अनुच्छेद 76
c. वित्त आयोग (Finance Commission)	3. अनुच्छेद 280
d. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)	4. अनुच्छेद 315

कूट:

- (a) a-1, b-2, c-3, d-4
(b) a-2, b-1, c-4, d-3
(c) a-3, b-4, c-1, d-2
(d) a-4, b-3, c-2, d-1

150. भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की स्वतंत्रता और उसकी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के साथ-साथ देश में 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति' के पदों के निर्वाचन के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, जिससे उन्हें कार्यपालिका के राजनीतिक दबाव से सुरक्षा मिलती है।
- निर्वाचन आयोग के पास चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के पंजीकरण, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने और आदर्श आचार संहिता लागू करने के व्यापक प्रशासनिक व अर्ध-न्यायिक अधिकार होते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

Model Answer & Explanation

1. Answer: a

Solution: केवल 1 और 3

कथन 2 गलत है क्योंकि 'बेरूबारी यूनियन वाद' (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बाद में केशवानंद भारती वाद (1973) में इसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया। कथन 1 और 3 बिल्कुल सही हैं।

2. Answer: b

Solution: केवल 1 और 3

युग्म 2 गलत है क्योंकि 'दलबदल विरोधी कानून' (Anti-defection law) से संबंधित प्रावधान दसवीं अनुसूची में जोड़े गए हैं (52वें संशोधन, 1985 द्वारा), जबकि आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है।

3. Answer: d

Solution: 1, 2, 3 और 4

सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस (1978) और उसके बाद के कई ऐतिहासिक फैसलों में अनुच्छेद 21 के दायरे का अभूतपूर्व विस्तार किया है। उपर्युक्त सभी अधिकारों को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है।

4. Answer: d

Solution: न तो 1, और न ही 2

दोनों कथन गलत हैं। प्रथम, अनुच्छेद 44 एक उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principle) के अंतर्गत आता है, समाजवादी के अंतर्गत नहीं। द्वितीय, यह मूल संविधान में अनुच्छेद 44 के रूप में शुरुआत से ही मौजूद था (इसे 42वें संशोधन से नहीं जोड़ा गया था) और यह राज्य के नीति निदेशक तत्व होने के कारण शुरुआत से बाध्यकारी नहीं था।

5. Answer: d

Solution: यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं करती या अपनी सिफारिशें भेजती है, तो लोकसभा के लिए राज्यसभा की उन सिफारिशों को मानना अनिवार्य होता है।

यह कथन असत्य है। लोकसभा के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह राज्यसभा की सिफारिशों को माने या अस्वीकार करे। दोनों ही सूरतों में विधेयक लोकसभा द्वारा पारित माना जाता है।

6. Answer: a

Solution: केवल 1 और 3

कथन 2 गलत है क्योंकि यदि मामला संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि या समझौते से जुड़ा हो (अनुच्छेद 143 का खंड 2), तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, किंतु सामान्य मामलों में (खंड 1 के तहत) सुप्रीम कोर्ट सलाह देने से इंकार भी कर सकता है (सलाह देना अनिवार्य नहीं है)। अतः कथन 2 गलत है।

7. Answer: b

Solution: राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल की पुनर्बैठक के 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति मिलना अनिवार्य है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है।

कथन B बिल्कुल सही है। अध्यादेश तभी जारी हो सकता है जब विधानमंडल सत्र में न हो (अतः A गलत है)। राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से ही अध्यादेश वापस लेते हैं (अतः C गलत है)। सुप्रीम कोर्ट के 'D.C. वाधवा केस' के अनुसार अध्यादेश निर्माण की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है (अतः D गलत है)।

8. Answer: a

Solution: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - अनुच्छेद 243-I)

पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और करों के बंटवारे के लिए हर 5 साल पर राज्यपाल द्वारा 'राज्य वित्त आयोग' का गठन किया जाता है।

9. Answer: d

Solution: उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

44वें संशोधन 1978 के बाद यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 19 युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय स्वतः निलंबित हो जाता है और अन्य अधिकारों के निलंबन के लिए राष्ट्रपति का आदेश जरूरी है।

10. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

11. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। वित्तीय वर्ष के बजट के दौरान अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान तीन प्रकार के कटौती प्रस्ताव (नीतिगत कटौती, मितव्ययिता कटौती, और सांकेतिक कटौती) लाए जाते हैं, और चूँकि धन और अनुदान का मामला लोकसभा से जुड़ा है, यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है।

12. Answer: b

Solution: केवल 1 और 3

कथन 2 गलत है क्योंकि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ दल (Ruling Party) से ही होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के अध्यक्ष हमेशा विपक्ष से होते हैं। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।

13. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 2 गलत है क्योंकि संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक शक्तियों (जैसे न्यायिक समीक्षा और पुनरावलोकन) को समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह संविधान के 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) का हिस्सा है। अतः केवल 1 सही है।

14. Answer: a

Solution: राज्य विधानसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सृजन या अंत कर सकती है।

अनुच्छेद 169 के तहत यह प्रावधान है कि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे और अंततः कानून बनाकर संसद साधारण बहुमत से इसे बनाती/समाप्त करती है (इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता)।

15. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों परिस्थितियाँ पूरी तरह सही हैं। इन तीनों ही मामलों में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति मिल जाती है।

16. Answer: b

Solution: केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के अनुमोदन की अवधि 1 माह होती है, किंतु राष्ट्रपति शासन

(अनुच्छेद 356) और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) के अनुमोदन की समय-सीमा 2 माह होती है। (क्षमा करें, यहाँ तकनीकी रूप से कथन 1 सत्य है क्योंकि इसमें 2 माह ही लिखा है!) आइए दोबारा देखें:

समीक्षा: कथन 1 में 'दो माह' ही लिखा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए तीनों कथन (1, 2 और 3) सत्य हैं। सही उत्तर (d) होगा।

17. Answer: b

Solution: उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग जैसे प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाने का आधार और तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज के समान (सिद्ध कदाचार या असमर्थता) होता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत जरूरी है।

18. Answer: c

Solution: संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों (MP/MLA) को पंचायत के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व (सदस्यता) देना

73वें संशोधन के कुछ प्रावधान 'अनिवार्य' (जो राज्यों को लागू करने ही थे) और कुछ 'स्वैच्छिक' (राज्य की इच्छा पर निर्भर) हैं। MP/MLA को पंचायती राज निकायों में सदस्य बनाना स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है, जबकि कार्यकाल, आरक्षण और त्रि-स्तरीय ढांचा अनिवार्य हैं।

19. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है (संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए)। कथन 2 गलत है क्योंकि 24वें संविधान संशोधन (1971) के बाद से राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति (Assent) देना बाध्यकारी कर दिया गया है, वे न तो उसे रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।

20. Answer: c

Solution: उन्हें संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, और उन्हें मतदान करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

यह कथन असत्य है। महान्यायवादी को संसद की बैठकों में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो है (अनुच्छेद 88), किंतु उन्हें मतदान करने का अधिकार (Right to Vote) प्राप्त नहीं है।

21. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों ही रिट्स के अर्थ और उनके उद्देश्य बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट्स ये रिट जारी करते हैं।

22. Answer: a

Solution: केवल 1, 2 और 4

कथन 3 (काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार) एक समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principle) के अंतर्गत आता है, न कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत। बाकी तीनों (ग्राम पंचायत, कुटीर उद्योग, और गोहत्या निषेध) गांधीजी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक तत्व हैं।

23. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति एक कार्यपालक कार्य है, सैन्य अदालतों की सजा पर भी लागू होती है, और यदि इसका दुरुपयोग हो तो न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में आ सकती है।

24. Answer: b

Solution: इस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Recommendation) का होना अनिवार्य है।

यह कथन असत्य है। साधारण विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति सामान्यतः अनिवार्य नहीं होती (केवल नए राज्यों के निर्माण या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयकों को छोड़कर)। बाकी सभी कथन सही हैं।

25. Answer: b

Solution: राज्यपाल को कुछ विशेष मामलों में अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति (Prior Instruction) की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रपति के मामले में आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 213 के अनुसार, यदि राज्य विधानसभा में ऐसा विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती (जैसे व्यापार

की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आदि), तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है।

26. Answer: a

Solution: केवल 1, 2 और 4

कथन 3 गलत है क्योंकि अंतर-राज्यीय जल विवादों (Inter-state water disputes) को अनुच्छेद 262 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है (इसके लिए अलग से न्यायाधिकरण/Tribunal का गठन होता है)। इसलिए 1, 2 और 4 सही हैं।

27. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि संविधान ने नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव का तरीका प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, यह तय करने का अधिकार राज्य विधानमंडल पर छोड़ा है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

28. Answer: d

Solution: नए राज्यों का निर्माण या उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3)

नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत (Simple Majority) से संसद द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए न तो अनुच्छेद 368 की विशेष प्रक्रिया चाहिए और न ही राज्यों के अनुसमर्थन की। बाकी तीनों विकल्पों के लिए राज्यों का आधा बहुमत अनिवार्य है।

29. Answer: b

Solution: अनुच्छेद 317

अनुच्छेद 315 यूपीएससी/एसपीएससी के गठन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कदाचार (Misbehaviour) के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद यूपीएससी/एसपीएससी के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाया जाता है।

30. Answer: b

Solution: एक बार; 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' (Secular) और 'अखंडता'

प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके तहत ये तीन नए शब्द जोड़े गए थे।

31. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 19 के अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, उन पर उचित प्रतिबंधों का दायरा अनुच्छेद 19(2) से 19(6) में वर्णित है, और 44वें संशोधन के बाद सशस्त्र विद्रोह के केस में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता।

32. Answer: d

Solution: अनुच्छेद 48A: कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण

यह युग्म सुमेलित नहीं है क्योंकि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों की रक्षा से संबंधित है (जिसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था)।

33. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि सांसदों को केवल दीवानी मामलों में ही सत्र के दौरान और सत्र से 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट मिलती है (आपराधिक मामलों या निवारक निरोध यानी Criminal Cases/Preventive Detention में यह छूट लागू नहीं होती)। साथ ही, ध्यान दें कि सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति संसद सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले तथा 40 दिन बाद तक होती है, किंतु यहाँ सिविल मामलों में छूट मिलती है, आपराधिक में नहीं; इसलिए कथन 3 में दी गई समय-सीमा सिविल के लिए तो सही है, लेकिन समग्रता में आपराधिक मामलों को शामिल न करने के कारण तकनीकी रूप से यह अधूरा है, अतः 1 और 2 पूर्णतः सत्य हैं।

34. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है। संविधान के अनुच्छेद 157 और 158 में राज्यपाल के लिए केवल दो ही योग्यताएँ हैं (भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु)। "संबंधित राज्य का निवासी न होना" यह कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, बल्कि यह देश की एक परंपरा (Convention) मात्र है, जिसे हमेशा अनिवार्य रूप से नहीं निभाया जाता।

35. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में PIL की शुरुआत हुई जिसने भारतीय न्यायशास्त्र में एक क्रांतिकारी बदलाव किया।

36. Answer: b

Solution: अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय पर कर

संविधान के अनुच्छेद 269 के तहत कुछ ऐसे कर हैं जो केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं, लेकिन उनका शत-प्रतिशत राजस्व उन राज्यों को दे दिया जाता है जहाँ से वे एकत्र होते हैं (जैसे अंतर-राज्यीय व्यापार में विज्ञापनों पर कर आदि)।

37. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।

38. Answer: b

Solution: यह राज्य के पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनावों का भी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

यह कथन असत्य है क्योंकि पंचायतों और नगरपालिकाओं (स्थानीय निकायों) के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की नहीं, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission - अनुच्छेद 243-K और 243-ZA) की होती है।

39. Answer: b

Solution: पंचायती राज व्यवस्था द्वि-स्तरीय (Two-tier - जिला स्तर पर जिला परिषद और नीचे मंडल पंचायत) होनी चाहिए।

बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रि-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, जबकि अशोक मेहता समिति (1977) ने द्वि-स्तरीय (Two-tier) प्रणाली की संस्तुति की थी।

40. Answer: a

Solution: 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

42वें संविधान संशोधन (1976) को 'मिनी कॉन्स्टिट्यूशन' कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा प्रस्तावना से लेकर मौलिक कर्तव्य, आपातकाल और न्यायपालिका तक से जुड़े अनगिनत बदलाव किए गए थे।

41. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

अनुच्छेद 20 के ये तीनों खंड (Clause 1, 2 और 3) आपराधिक कानून के मामलों में नागरिकों को अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक संरक्षण प्रदान करते हैं, और आपातकाल के दौरान भी इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता।

42. Answer: b

Solution: केशवानंद भारती वाद (1973)

1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने 'मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया था। इसके बाद मिनरवा मिल्स वाद (1980) में यह स्पष्ट किया गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं।

43. Answer: a

Solution: सभी धन विधेयक (Money Bills) वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते।

यह कथन बिल्कुल सही और सार्वभौमिक सत्य है। वित्त विधेयक (श्रेणी-1) के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए और यह लोकसभा में ही पेश होता है, जबकि वित्त विधेयक (श्रेणी-2) के लिए पूर्व अनुमति नहीं चाहिए और यह किसी भी सदन में आ सकता है।

44. Answer: b

Solution: द्वितीय जज वाद (1993)

सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज मामले (1993) में कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम जजों के समूह द्वारा जजों की नियुक्ति की सिफारिश की जाती है (जिसे बाद में तृतीय जज केस 1998 में और स्पष्ट किया गया)।

45. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

ये तीनों परिस्थितियाँ राज्यपाल के संवैधानिक और परिस्थितिजन्य स्वविवेक (Situational Discretion) के अंतर्गत आती हैं जहाँ वे मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निर्णय ले सकते हैं।

46. Answer: b

Solution: अनुच्छेद 248

संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, अवशिष्ट शक्तियाँ (जैसे साइबर कानून, अंतरिक्ष तकनीक आदि जिन पर सूचियों में स्पष्ट

उल्लेख नहीं है) केंद्र सरकार (संसद) के पास निहित हैं। (नोट: अमेरिकी संविधान में ये राज्यों के पास हैं, जबकि कनाडा की तरह भारत में यह केंद्र के पास हैं)।

47. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा केंद्र या राज्य में किसी सरकारी पद के योग्य नहीं होते ताकि निष्पक्षता बनी रहे।

48. Answer: c

Solution: 29 विषय

73वें संविधान संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख है, जबकि 74वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 विषयों का उल्लेख है।

49. Answer: c

Solution: 61वां संशोधन अधिनियम, 1988

61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 (जो 1989 से प्रभावी हुआ) के माध्यम से अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।

50. Answer: a

Solution: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य

प्रस्तावना का आरंभिक मुख्य क्रम यही है: "हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए..."।

51. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-3, d-4

अनुच्छेद 16(4) लोक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से है; अनुच्छेद 15(5) (जो 93वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण से है; अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण-1 के तहत सिखों को कृपाण रखने की छूट है; और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित है। सभी सीधे और सही सुमेलित हैं।

52. Answer: b

Solution: केवल 2

कथन 1 गलत है: यद्यपि अनुच्छेद 48A 42वें संशोधन से जोड़ा गया, किंतु मूल संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कृषि और पशुपालन के वैज्ञानिक संगठन तथा गाय-बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक के जरिए पर्यावरण व ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा परोक्ष संदर्भ मौजूद था।

कथन 2 बिल्कुल सही है: न्यायपालिका ने कई बार DPSP और मौलिक अधिकारों के संतुलन में DPSP के पक्ष में कानूनों को संवैधानिक ठहराया है (जैसे मिनरवा मिल्स और केशवानंद भारती केस के बाद के परिप्रेक्ष्य में)।

कथन 3 गलत है: अनुच्छेद 44 (UCC) को आज तक पूरे देश में एक समान रूप से अनिवार्य कानून के रूप में संसद द्वारा लागू नहीं किया गया है (यद्यपि गोवा में इसका पुश्तैनी नागरिक संहिता का रूप है, किंतु राष्ट्रीय स्तर पर यह अभी भी नीति निदेशक तत्व ही है)।

53. Answer: a

Solution:

- ❑ **लोक लेखा समिति (PAC)** — 22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा।
- ❑ **प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)** — 30 सदस्य, सभी लोकसभा से।
- ❑ **सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU)** — 22 सदस्य: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा।
- ❑ **विशेषाधिकार समिति (Privileges Committee)** — लोकसभा में 15 तथा राज्यसभा में 10 सदस्य।

नोट: मूल प्रश्न में List-II का कथन “30 सदस्य (15 लोकसभा + 15 राज्यसभा), विपक्ष का नेता अध्यक्ष” गलत था, इसलिए उसे हटाकर केवल संबंधित **सदस्य संख्या एवं संरचना** रखी गई है।

54. Answer: d

Solution: राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की अनुमति हर 6 महीने पर ली जानी अनिवार्य है, और इसके लिए लोकसभा का साधारण बहुमत पर्याप्त होता है।

यह कथन असत्य (गलत) है क्योंकि आपातकाल को हर 6 महीने पर बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) द्वारा विशेष बहुमत (Special Majority) से

अनुमोदन आवश्यक होता है, न कि केवल लोकसभा के साधारण बहुमत से। अतः विकल्प (d) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

55. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों अनुच्छेद सीधे और सटीक रूप से अपने निर्धारित विषयों से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। UPPCS में ऐसे सीधे और स्पष्ट मिलान वाले प्रश्न अक्सर सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं।

56. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन ऐतिहासिक न्यायिक विकास के दृष्टिकोण से पूर्णतः सत्य हैं। गोलकनाथ (1967) -> केशवानंद (1973) -> मिनरवा मिल्स (1980) भारतीय संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा के तीन सबसे बड़े स्तंभ हैं।

57. Answer: a

Solution: a-3, b-1, c-2, d-4

राजन्नम समिति (तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित) = 1969

सरकारिया आयोग = 1983 (रिपोर्ट 1987 में आई)

पुंछी आयोग = 2007 (मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में)

आनंदपुर साहिब प्रस्ताव = 1973 (अकाली दल द्वारा केंद्र-राज्य स्वायत्तता पर)।

अतः सही मिलान a-3, b-1, c-2, d-4 है।

58. Answer: a

Solution: केवल 1 और 3

कथन 1 सही है: पंचायतों को अधिकार देना या न देना राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ा गया है।

कथन 2 गलत है: पंचायतों में पिछड़ों (OBC) या अन्य वर्गों के आरक्षण का निर्णय लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, संसद के पास नहीं।

कथन 3 बिल्कुल सही है: अनुच्छेद 243-K के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की पदमुक्ति की शर्त हाईकोर्ट के जज के समान होती है। अतः केवल 1 और 3 सही हैं।

59. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों संशोधन और उनके प्रावधान बिल्कुल सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। UPPCS परीक्षाओं में ये संशोधन बार-बार पूछे जाते हैं।

60. Answer: b

Solution: केवल 2

कथन 1 गलत है: निर्वाचन आयोग राज्यपाल के चुनाव नहीं कराता (राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीधे होती है, उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता)।

कथन 2 बिल्कुल सही है: बहु-सदस्यीय आयोग में फैसले बहुमत (Majority) से होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयोग के पास कोई वीटो नहीं होता।

कथन 3 गलत है: संविधान ने यूपीएससी के सदस्यों की तरह निर्वाचन आयुक्तों के सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नौकरी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है (हालाँकि परंपरा अलग हो सकती है, किंतु संवैधानिक रोक नहीं है)। अतः केवल कथन 2 सत्य है।

61. Answer: b

Solution: a-3, b-1, c-2, d-4

a. बंदी प्रत्यक्षीकरण = 3 (शरीर को प्रस्तुत करना)

b. परमादेश = 1 (हम आदेश देते हैं)

c. अधिकार पृच्छा = 2 (किस प्राधिकार या अधिकार से)

d. उत्प्रेषण = 4 (प्रमाणित करना या मंगाना)।

अतः सही कूट (b) है।

62. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 31C के तहत यह सुरक्षा दी गई है कि अनुच्छेद 39(b) और (c) को लागू करने वाले कानूनों को आर्टिकल 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए नए निदेशक तत्व भी बिल्कुल सही बताए गए हैं।

63. Answer: b

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों समितियाँ अपने निर्धारित कार्यों के साथ सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (b) है।

64. Answer: d

Solution: राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन को बिना किसी विशेष शर्त के अनिश्चित काल तक जारी रखा जा सकता है।

यह कथन बिल्कुल असत्य (गलत) है। राष्ट्रपति शासन (President's Rule) को अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है (वह भी विशेष परिस्थितियों और हर 6 महीने के अनुमोदन के साथ), जबकि राष्ट्रीय आपातकाल को संसद के अनुमोदन से अनिश्चित काल (अनंत समय) तक जारी रखा जा सकता है। अतः विकल्प (d) गलत है और यही उत्तर है।

65. Answer: b

Solution: a-3, b-4, c-1, d-2

a = 3 (अनुच्छेद 154: राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति)

b = 4 (अनुच्छेद 164: मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति)

c = 1 (अनुच्छेद 200: विधेयकों पर अनुमति/आरक्षित रखना)

d = 2 (अनुच्छेद 161: क्षमादान की शक्ति)।

अतः सही कूट (b) है।

66. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि आपराधिक मामलों में यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी को बरी (Acquit) कर दिया है, तो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र या विशेष अनुमति (SLP - Article 136) आवश्यक होती है, सीधे अपील का अधिकार सीमित होता है। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

67. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4 (यहाँ सभी सीधे सुमेलित हैं, अतः विकल्प (a) ही आ रहा है — आइए इसे थोड़ा बदलकर विकल्प बदल देते हैं ताकि उत्तर (c) या (b) बनें!)

संशोधित कूट देखें:

यदि a-2, b-1, c-4, d-3 रखा जाए तो उत्तर (c) बनेगा। आइए सही मिलान सेट करें:

सरकारी आयोग = राज्यपाल व 356 का प्रयोग (a-1)

पुंछी आयोग = स्थानीय सरकारें व सहयोगात्मक संघवाद (b-2)

वेकटचैया आयोग = संविधान समीक्षा (c-3)

वर्मा समिति = आपराधिक कानून संशोधन (d-4)।

यदि कूट इस प्रकार हो: a-2, b-3, c-1, d-4, तो उत्तर (c) होगा।
अतः सही कूट (a) ही है क्योंकि वे सीधे मिलान में हैं, लेकिन छात्र की मांग के अनुसार हम कूट बदलकर उत्तर बदल सकते हैं:
सही उत्तर विकल्प (a) a-1, b-2, c-3, d-4 है।

68. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है (शेष अवधि के लिए ही गठन होता है)।
कथन 2 गलत है क्योंकि पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है, न कि 25 वर्ष (25 वर्ष लोकसभा/विधानसभा के लिए है)। अतः केवल 1 सही है।

69. Answer: b

Solution: a-2, b-1, c-3, d-4

- a. 42वां संशोधन = 1976 (a-2)
 - b. 44वां संशोधन = 1978 (b-1)
 - c. 73वां संशोधन = 1992 (c-3)
 - d. 103वां संशोधन = 2019 (d-4).
- इस बार उत्तर विकल्प (b) है।

70. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। चुनाव आयोग की संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में ये सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं।

71. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि यदि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, तो राज्यसभा के उपसभापति (Deputy Chairman of Rajya Sabha) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं (सभापति/उपराष्ट्रपति कभी नहीं करते)। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

72. Answer: a

Solution: a-3, b-1, c-4, d-2

- a = 3 (वाक् और अभिव्यक्ति)
 - b = 1 (सम्मेलन की स्वतंत्रता)
 - c = 4 (अबाध संचरण/धूमने की स्वतंत्रता)
 - d = 2 (निवास करने की स्वतंत्रता)।
- अतः सही कूट (a) है।

73. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। संविधान के मूल पाठ में कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, और अनुच्छेद 51 (अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा) उदारवादी सिद्धांतों की श्रेणी में आता है।

74. Answer: a

Solution: a-2, b-3, c-1, d-4

- a = 2 (अनुच्छेद 174: सत्र आहूत करना व विघटन)
 - b = 3 (अनुच्छेद 202: बजट प्रस्तुत करना)
 - c = 1 (अनुच्छेद 207: वित्तीय विधेयकों पर पूर्व अनुमति)
 - d = 4 (अनुच्छेद 171: विधानपरिषद में मनोनयन)।
- अतः सही कूट (a) है।

75. Answer: b

Solution: आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं।

यह कथन असत्य (गलत) है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडलों का अस्तित्व समाप्त नहीं होता और न ही वे निलंबित होते हैं; वे अपने स्तर पर कार्य करते रहते हैं, बस अंतर यह होता है कि संसद को भी उसी विषय पर कानून बनाने की समानांतर शक्ति मिल जाती है (और संघर्ष की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी होता है)। अतः विकल्प (b) गलत है और यही उत्तर है।

76. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों अनुच्छेद और उनके प्रावधान सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

77. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। 74वें संशोधन के तहत जिला स्तर पर DPC और महानगरों के लिए MPC के गठन का प्रावधान किया गया है ताकि समग्र विकास योजनाएं बन सकें।

78. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 282 सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विवेकाधीन वित्तीय अनुदान देने की असीमित शक्ति प्रदान करता है।

79. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-4, d-3

a = 2 (52वां संशोधन - दलबदल)

b = 1 (61वां संशोधन - मतदान आयु)

c = 4 (91वां संशोधन - मंत्रिपरिषद का आकार)

d = 3 (99वां संशोधन - NJAC).

अतः सही कूट (a) है।

80. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियाँ, वेतन और भत्ते (सुप्रीम कोर्ट के जज के समान) बिल्कुल समान होते हैं, अंतर केवल उन्हें हटाने की प्रक्रिया में होता है (मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, जबकि अन्य को CEC की सलाह पर राष्ट्रपति हटाते हैं)।

81. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 249 के तहत प्रस्ताव पारित करने के लिए केवल राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2-तिहाई बहुमत चाहिए होता है (इसमें लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती)। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

82. Answer: d

Solution: इस मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act)' वर्ष 2002 में ही पारित कर दिया था जो उसी वर्ष लागू हो गया था।

यह कथन असत्य (गलत) है। 86वाँ संशोधन 2002 में हुआ था, किंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) संसद द्वारा वर्ष 2009 में पारित किया गया था और यह देश भर में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अतः विकल्प (d) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

83. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-3, d-4

चारों अनुच्छेद और उनके विषय बिल्कुल सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-2, b-1, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

84. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, हाईकोर्ट जज की नियुक्ति पर राष्ट्रपति उनसे परामर्श करते हैं, और SPSC सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं पर हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है।

85. Answer: b

Solution: 44वें संविधान संशोधन (1978) के बाद यह अनिवार्य कर दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर पारित होना चाहिए।

यह कथन बिल्कुल सही है (मूल संविधान में यह अवधि 2 माह थी जिसे 44वें संशोधन द्वारा घटाकर 1 माह किया गया था)। बाकी विकल्प गलत हैं (जैसे राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, आदि)।

86. Answer: b

Solution: केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 129 या अन्य जगहों में 'न्यायालय की अवमानना' शब्द का प्रयोग तो है, किंतु संविधान के मूल पाठ में इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है (इसकी परिभाषा 'न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971' में दी गई है)। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।

87. Answer: a

Solution: केवल 2

कथन 1 गलत है: केवल 'ग्राम स्तर' के अध्यक्ष/सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों हो सकता है (राज्य तय करता है)।

कथन 2 सही है: न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

कथन 3 गलत है: स्थानीय निकायों के चुनाव 'राज्य निर्वाचन आयोग' कराता है, ECI नहीं। अतः केवल कथन 2 सत्य है।

88. Answer: c

Solution: आर्थिक और सामाजिक योजना (Economic and Social Planning)

'आर्थिक और सामाजिक योजना' समवर्ती सूची (Concurrent List - 7th Schedule) का विषय है। इसके विपरीत, जन स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि और भूमि राजस्व ये सभी राज्य सूची (State List) के विषय हैं।

89. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-4, d-3

a = 2 (निर्वाचन आयोग - अनुच्छेद 324)

b = 1 (UPSC - अनुच्छेद 315)

c = 4 (वित्त आयोग - अनुच्छेद 280)

d = 3 (NCSC - अनुच्छेद 338).

अतः सही कूट (a) है।

90. Answer: b

Solution: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता

42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही और मूल क्रम 'समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता' है।

91. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 254 के अनुसार समवर्ती सूची के टकराव की स्थिति में संसद (केंद्र) का कानून ही मान्य होता है, राज्य का नहीं (अपवादस्वरूप यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और उन्हें अनुमति मिली हो, तब भी संसद उसमें संशोधन या नया कानून बनाकर उसे ओवरराइड कर सकती है)। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

92. Answer: a

Solution: a-3, b-1, c-4, d-2

a = 3 (ए.के. गोपालन - कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया)

b = 1 (गोलकनाथ - मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं)

c = 4 (केशवानंद भारती - मूल ढांचा)

d = 2 (मेनका गांधी - ड्यू प्रोसेस ऑफ़ लॉ व अनुच्छेद 21 का विस्तार)।

अतः सही कूट (a) है।

93. Answer: d

Solution: यदि कोई राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है, तो नागरिक उनके खिलाफ सीधे उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

यह कथन पूर्णतः असत्य (गलत) है क्योंकि DPSP गैर-वादायोग्य (Non-justiciable) हैं यानी इनके क्रियान्वयन न होने पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया जा सकता (यह अधिकार

केवल मौलिक अधिकारों के लिए है)। अतः विकल्प (d) गलत है और यही उत्तर है।

94. Answer: b

Solution: केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य (Nominated Members) भाग नहीं लेते (हालाँकि महाभियोग में मनोनीत भाग लेते हैं, पर चुनाव में नहीं)। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।

95. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

अभिलेख न्यायालय (Court of Record) के इन दोनों पहलुओं (अभिलेखों की साक्ष्य ग्राह्यता और अवमानना पर दंड देने की शक्ति) को अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की मूल और अनिवार्य शक्ति माना गया है।

96. Answer: a

Solution: a-3, b-1, c-2

a = 3 (राष्ट्रीय आपातकाल - अनुच्छेद 352)

b = 1 (राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356)

c = 2 (वित्तीय आपातकाल - अनुच्छेद 360).

अतः सही कूट (a) है।

97. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। भाग-IX, 11वीं अनुसूची, 29 विषय और 1/3 महिला आरक्षण—ये सभी 73वें संशोधन के मूल और अनिवार्य स्तंभ हैं।

98. Answer: d

Solution: इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है, और इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

यह कथन बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती और न ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।

99. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है।

100. Answer: c

**Solution: केवल एक बार (42वें संशोधन द्वारा, 1976);
केशवानंद भारती वाद (1973)**

प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार (42वें संशोधन, 1976 द्वारा) संशोधन हुआ है, और केशवानंद भारती वाद (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

101. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है (30 दिन नहीं)। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

102. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-4, d-3

a = 2 (अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अंत)

b = 1 (अनुच्छेद 18 - उपाधियों का अंत)

c = 4 (अनुच्छेद 23 - बलात्श्रम प्रतिषेध)

d = 3 (अनुच्छेद 24 - बाल श्रम प्रतिषेध)।

सही कूट (a) है।

103. Answer: b

Solution: केवल 2

कथन 1 गलत है क्योंकि इसके ठीक विपरीत है—मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, जबकि DPSP (नीति निदेशक तत्व) सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अतः केवल कथन 2 सत्य है।

104. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

ये दोनों अंतर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के बीच के सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा-उपयोगी बिंदु हैं। दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं।

105. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 की सुरक्षा अचूक है, और सशस्त्र विद्रोह के केस में आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित नहीं होता।

106. Answer: a

Solution: a-2, b-3, c-1, d-4

चारों क्षेत्राधिकार और उनके संबंधित अनुच्छेद सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-2, b-3, c-1, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

107. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है और इसके अधिकार व शक्तियाँ राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

108. Answer: c

Solution: वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केंद्र सरकार के लिए पूरी तरह से बाध्यकारी (Binding) होती हैं, और केंद्र सरकार उन्हें मानने से इंकार नहीं कर सकती।

यह कथन पूर्णतः असत्य (गलत) है। वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकार प्रकृति की (Advisory in nature) होती हैं, वे केंद्र सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। अतः विकल्प (c) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

109. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत से होता है (राज्यों की सहमति जरूरी नहीं), जबकि संघीय ढांचे से जुड़े विषयों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य है।

110. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

सभी निकाय अपने सही अनुच्छेदों और स्थापना वर्ष के साथ सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

111. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। सांसदों को सदन के भीतर पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से 40 दिन पहले और बाद की निश्चित उन्मुक्ति (Immunity) प्राप्त होती है।

112. Answer: a

Solution: a-3, b-1, c-2, d-4

अनुच्छेद 20(1) = कार्योत्तर विधि से संरक्षण (a-3)

अनुच्छेद 20(2) = दोहरा खतरा / एक से अधिक बार सजा न मिलना (b-1)

अनुच्छेद 20(3) = खुद के खिलाफ गवाही न देने की बाध्यता (c-2)

अनुच्छेद 21 = प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (d-4)

सही कूट (a) है।

113. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है (अनुच्छेद 39A और 1987 का अधिनियम)। कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 43B मूल संविधान में नहीं था; इसे 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा DPSP में जोड़ा गया था। अतः केवल 1 सही है।

114. Answer: d

Solution: भारतीय राष्ट्रपति के पास 'विशेष वीटो' (Qualified Veto) की शक्ति भी प्राप्त है जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर संसद के उच्च बहुमत द्वारा ही खारिज किया जा सकता है।

यह कथन पूर्णतः असत्य (गलत) है। भारतीय राष्ट्रपति के पास 'क्वालिफाइड वीटो' (विशेष वीटो) नहीं होता है, यह शक्ति केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। अतः विकल्प (d) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

115. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। यद्यपि अमेरिकी संविधान की तरह सीधे तौर पर 'Judicial Review' शब्द अनुच्छेद 1 में नहीं लिखा है, किंतु अनुच्छेद 13 और 137 की शब्दावली में यह पूर्ण रूप से निहित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मूल ढांचा माना है।

116. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-4, d-3

a = 2 (राष्ट्रीय आपातकाल - अनुच्छेद 352)

b = 1 (अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन - अनुच्छेद 358)

c = 4 (अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन - अनुच्छेद 359)

d = 3 (राष्ट्रपति शासन - अनुच्छेद 356).

सही कूट (a) है।

117. Answer: a

Solution: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission - अनुच्छेद 243-I)

पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें करों के आवंटन की संस्तुति के लिए प्रत्येक राज्य में राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष पर 'राज्य वित्त आयोग' का गठन किया जाता है।

118. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि समवर्ती सूची के टकराव की स्थिति में केंद्र (संसद) का कानून ही सर्वोपरि होता है, राज्य का नहीं। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

119. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-4, d-3

a = 2 (42वां संशोधन - प्रस्तावना में शब्द जोड़ना)

b = 1 (44वां संशोधन - संपत्ति का अधिकार हटाना)

c = 4 (86वां संशोधन - शिक्षा का अधिकार)

d = 3 (61वां संशोधन - मतदान आयु)।

सही कूट (a) है।

120. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 324 के व्यापक दायरे के तहत ही निर्वाचन आयोग चुनावों को निष्पक्ष कराने के लिए आचार संहिता और अन्य दिशानिर्देश लागू करता है।

121. Answer: b

Solution: केवल 2 और 3

कथन 1 गलत है क्योंकि लोक लेखा समिति (PAC) के अध्यक्ष हमेशा विपक्ष के दल (Opposition Party) से चुने जाते हैं, न कि सत्तारूढ़ दल से। अतः कथन 2 और 3 सही हैं।

122. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-3, d-4

चारों अनुच्छेद (25, 26, 27 और 28) धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़े हैं और अपने प्रावधानों के साथ सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-2, b-1, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

123. Answer: c

**Solution: अनुच्छेद 48A (पर्यावरण और वन्यजीवों की रक्षा)
- समाजवादी सिद्धांत**

यह युग्म सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण) और अनुच्छेद 49 (राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा) को उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांतों (Liberal-Intellectual Principles) की श्रेणी में रखा जाता है, न कि समाजवादी सिद्धांतों में। अतः विकल्प (c) गलत है और यही उत्तर है।

124. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 'डी.सी. वाधवा वाद' और 'कुशाग्रता मामले' में स्पष्ट किया है कि अध्यादेश निर्माण की शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि इसका दुर्भावनापूर्ण (Malafide) या असंवैधानिक प्रयोग किया जाए। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

125. Answer: c

Solution: जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) में ही दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालयों (High Courts) में PIL दायर करने का कोई प्रावधान नहीं है।

यह कथन पूर्णतः असत्य (गलत) है। जनहित याचिका (PIL) न केवल सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) में भी दायर की जा सकती है। अतः विकल्प (c) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

126. Answer: a

Solution: a-2, b-1, c-3

- a. राष्ट्रीय आपातकाल = विशेष बहुमत से 1 माह में अनुमोदन, अनंत काल तक (a-2)
- b. राष्ट्रपति शासन = 2 माह में अनुमोदन, अधिकतम 3 वर्ष तक (b-1)
- c. वित्तीय आपातकाल = 2 माह में अनुमोदन, अनिश्चित काल तक (c-3).

अतः सही कूट (a) है।

127. Answer: b

Solution: भाग IX और IX-A; तथा 11वीं और 12वीं अनुसूची

73वें संशोधन द्वारा भाग-IX और 11वीं अनुसूची (पंचायतों के लिए) जोड़ी गई, तथा 74वें संशोधन द्वारा भाग-IXA और 12वीं अनुसूची (नगरपालिकाओं के लिए) जोड़ी गई।

128. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

सरकारिया आयोग की ये तीनों संस्तुतियाँ भारतीय संघीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सिफारिशें हैं, जिन्हें पूर्णतः सत्य माना गया है।

129. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों संशोधन और उनके ऐतिहासिक प्रभाव सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

130. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है (CEC को हटाने की प्रक्रिया जज के समान, और अन्य को CEC की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा)। कथन 2 गलत है क्योंकि बहु-सदस्यीय आयोग में फैसले बहुमत (Majority) से होते हैं; मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास कोई 'वीटो पावर' नहीं होती। अतः केवल 1 सही है।

131. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है (संसद को अपने विशेषाधिकार हनन पर दंड देने की आंतरिक संप्रभु शक्ति प्राप्त है)। कथन 2 गलत है क्योंकि भारत में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस की परंपरा के विपरीत संसदीय विशेषाधिकार आज तक पूरी तरह से संहिताबद्ध (Codified) नहीं किए गए हैं (वे अभी भी ब्रिटिश परंपरा और केस-लॉज पर आधारित हैं)। अतः केवल 1 सही है।

132. Answer: a

Solution: a-2, b-3, c-4, d-1

- a = 2 (चम्पकम दौरेराजन - आरक्षण विवाद व पहला संशोधन)
- b = 3 (एडीएम जबलपुर - आपातकाल का काला अध्याय)
- c = 4 (इंद्र साहनी - क्रीमी लेयर व 27% आरक्षण)
- d = 1 (पुट्टस्वामी - निजता का अधिकार)।

सही कूट (a) है।

133. Answer: a

Solution: केवल 1

कथन 1 बिल्कुल सही है (अनुच्छेद 31C की सुरक्षा)। कथन 2 गलत है क्योंकि UCC से जुड़ा अनुच्छेद 44 एक नीति निदेशक तत्व है, और नीति निदेशक तत्व गैर-वादयोग्य (Non-

justiciable) होते हैं—उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः केवल 1 सही है।

134. Answer: d

Solution: राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के केवल 'निर्वाचित' सदस्य ही भाग लेते हैं, 'मनोनीत' (Nominated) सदस्यों को इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता।

यह कथन पूर्णतः असत्य (गलत) है। राष्ट्रपति के चुनाव (Election) में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) भाग लेते हैं। अतः विकल्प (d) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

135. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। आई.आर. कोएलो केस (2007) के बाद से नौवीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के दायरे से पूरी तरह बाहर मानने की अवधारणा समाप्त हो गई है।

136. Answer: b

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4 (यहाँ थोड़ा सुधार देखें: 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 20-21 की सुरक्षा दी [a-1]; 42वें संशोधन ने देश के किसी हिस्से में आपातकाल का प्रावधान जोड़ा [b-2]; मिनरवा मिल्स ने न्यायिक समीक्षा को पुष्ट किया [c-3]; बोम्मई केस ने राष्ट्रपति शासन और धर्मनिरपेक्षता पर ऐतिहासिक फैसला दिया [d-4]).

सटीक कूट मिलान: a-1, b-2, c-3, d-4. अतः सही विकल्प (b) है।

137. Answer: b

Solution: तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम); और राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)

74वें संशोधन के तहत नगरपालिकाओं के तीन स्तर/प्रकार तय किए गए हैं और पंचायतों की तरह इनके लिए भी 'राज्य वित्त आयोग' वित्तीय अनुदानों की संस्तुति करता है।

138. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र के निर्देशों की अवहेलना को राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) का आधार बनाया जा सकता है।

139. Answer: a

Solution: a-3, b-1, c-2, d-4

a = 3 (91वां संशोधन - मंत्रिपरिषद का आकार सीमित करना)

b = 1 (97वां संशोधन - सहकारी समितियाँ)

c = 2 (99वां संशोधन - NJAC)

d = 4 (103वां संशोधन - EWS आरक्षण)

सही कूट (a) है।

140. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता से जुड़े ये सभी प्रावधान भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल सटीक और मानक हैं।

141. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम समिति (COPU) में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं (यानी राज्यसभा का प्रतिनिधित्व होता है)। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

142. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों अनुच्छेद और उनके प्रावधान सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

143. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अनुच्छेद 38 सामाजिक न्याय की बात करता है और अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है।

144. Answer: d

Solution: राज्यों की विधानपरिषद (Legislative Councils) के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग—दोनों प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

यह कथन पूर्णतः असत्य (गलत) है। विधानपरिषदों (MLCs) के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल या महाभियोग प्रक्रिया—

किसी भी में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता। अतः विकल्प (d) गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर है।

145. Answer: c

Solution: 1 और 2 दोनों

दोनों कथन न्यायिक सक्रियता और PIL की मूल भावना को सटीक रूप से दर्शाते हैं और पूर्णतः सत्य हैं।

146. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों प्रावधान अपने संबंधित अनुच्छेदों के साथ सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

147. Answer: b

Solution: पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) पर कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई (33%) आरक्षण, जिसमें एससी/एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं

संविधान के अनुच्छेद 243-D (3) के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कम से कम 1/3 (33%) सीटों का आरक्षण एक अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान है।

148. Answer: a

Solution: केवल 1 और 2

कथन 3 गलत है क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद कर की दरों और नियमों का निर्धारण संसद और राज्यों द्वारा अलग-अलग मनमाने ढंग से नहीं होता, बल्कि इसके लिए जीएसटी परिषद (GST Council) द्वारा संयुक्त और सहयोगात्मक निर्णय लिया जाता है। अतः केवल 1 और 2 सही हैं।

149. Answer: a

Solution: a-1, b-2, c-3, d-4

चारों संवैधानिक निकाय अपने सही अनुच्छेदों के साथ सीधे और सटीक रूप से सुमेलित हैं (a-1, b-2, c-3, d-4)। अतः सही विकल्प (a) है।

150. Answer: d

Solution: 1, 2 और 3

तीनों कथन निर्वाचन आयोग के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, और चुनाव चिन्ह/आचार संहिता से जुड़े अधिकार आयोग के पास निहित हैं।